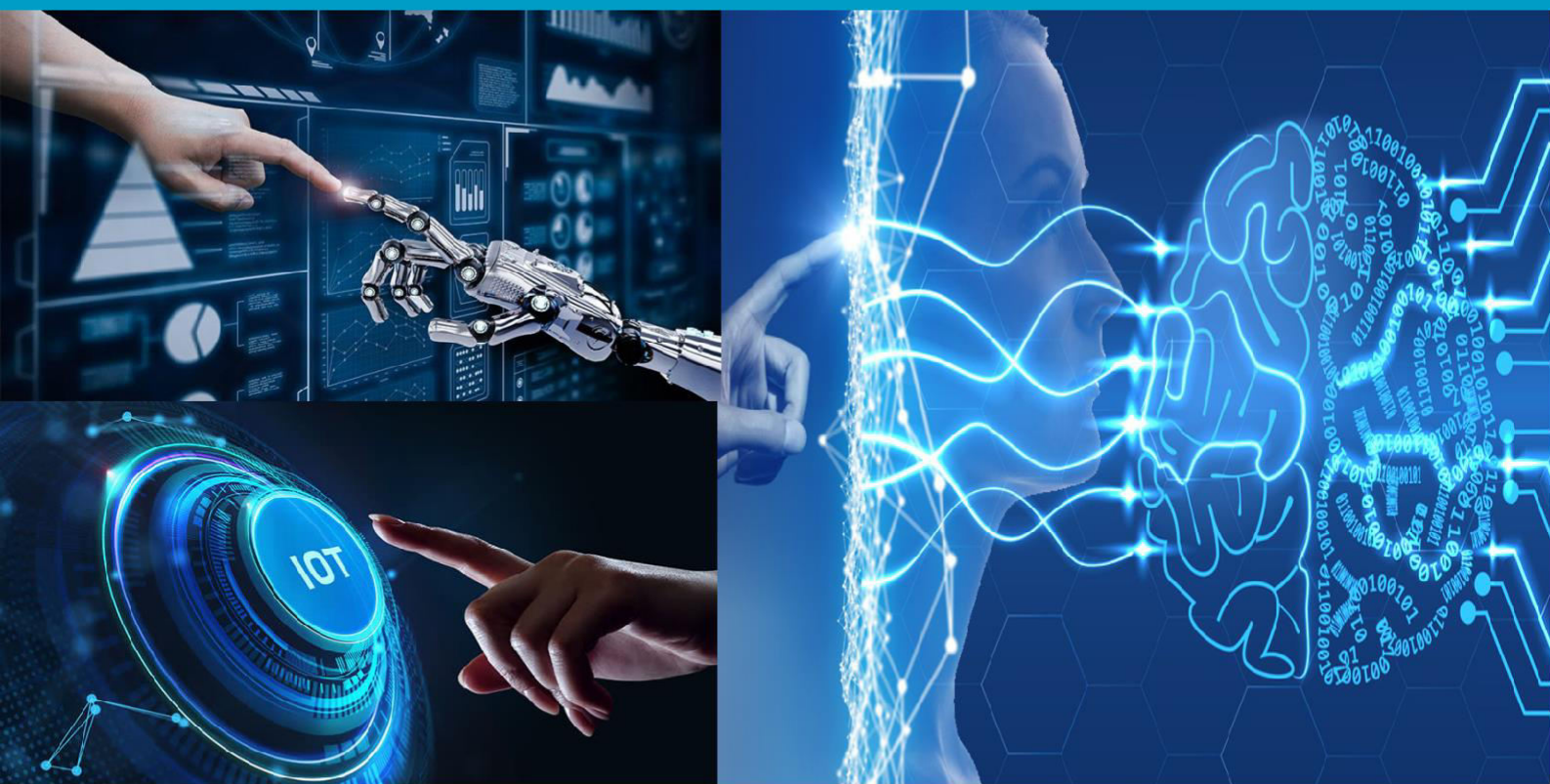




INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 10, Issue 10, October 2023



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.580



+91 99405 72462



+9163819 07438



ijmrsetm@gmail.com



www.ijmrsetm.com

गलवान गतिरोध के बाद भारत द्वारा चीनी ऐप्स पर प्रतिबन्ध और भारत-चीन संबंध

LAL CHAND MEENA

Assistant Professor, Political Science, S.B.D. Government College, Sardarshahar, Rajasthan, India

सार

5 मई 2020 से शुरू होकर, चीनी और भारतीय सैनिक चीन-भारत सीमा पर स्थानों पर आक्रामक हाथापाई, आमना-सामना और झड़पों में लगे रहे, जिसमें लद्दाख और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में विवादित पैंगोंग झील के पास और सिक्किम के बीच की सीमा भी शामिल है। और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास पूर्वी लद्दाख में स्थानों पर अतिरिक्त झड़पें भी हुईं। मई के अंत में चीनी सेना ने गलवान नदी घाटी में भारतीय सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई थी।^{[45] [46]} भारतीय सूत्रों के अनुसार, 15-16 जून 2020 को हाथापाई की लड़ाई में चीनी और भारतीय सैनिकों की मौत हुई।^{[47] [48] [36]} मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि दोनों पक्षों के सैनिकों को बंदी बना लिया गया और आने वाले कुछ दिनों में रिहा कर दिया जाएगा, जबकि दोनों पक्षों के आधिकारिक सूत्र इस बात से इनकार करते रहे।^{[25] [38] [49]} 7 सितंबर को, 45 वर्षों में पहली बार, एलएसी पर गोलीबारी हुई, दोनों पक्षों ने गोलीबारी के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया।^{[50] [51]} भारतीय मीडिया ने यह भी बताया कि भारतीय सैनिकों ने 30 अगस्त को पीएलए पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं।^[52]

परिचय

गलवान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा से आंशिक विघटन जून-जुलाई 2020 में हुआ, जबकि पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट से पूर्ण विघटन फरवरी 2021 में हुआ।^{[53] [54]} अगस्त 2021 में गोगरा में विघटन के बाद, भारतीय विश्लेषकों ने बताया कि एलएसी गश्त बिंदु 17ए (पीपी 17ए) पर पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई है।^{[55] [56]} गतिरोध के बीच, भारत ने लगभग 12,000 अतिरिक्त श्रमिकों के साथ इस क्षेत्र को मजबूत किया, जो चीन-भारत सीमा पर भारतीय बुनियादी ढांचे के विकास को पूरा करने में भारत के सीमा सड़क संगठन की सहायता करेंगे।^{[57] [58] [59]} विशेषज्ञों ने माना है कि गतिरोध लद्दाख में दारबुक-श्योक-डीबीओ रोड बुनियादी ढांचा परियोजना के जवाब में चीनी पूर्व-खाली उपाय हैं।^[60] चीन ने भी इन विवादित सीमा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अपना बुनियादी ढांचा विकसित किया है और ऐसा करना जारी रख रहा है।^{[61] [62]} भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने से भी चीन परेशान है।^[63] हालांकि, भारत और चीन दोनों ने कहा है कि स्थिति को हल करने के लिए पर्याप्त द्विपक्षीय तंत्र हैं।^{[64] [65]} इसमें कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक की बातचीत के कई दौर, विशेष प्रतिनिधियों की बैठकें,^{[66] [67] [68]} चीन-भारत सीमा पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की बैठकें शामिल हैं। मामले ' (डब्ल्यूएमसीसी),^[69] और उनके संबंधित विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच बैठकें और संचार।^[71] 12 जनवरी 2022 को, चुशुल-मोल्डो सीमा कार्मिक बैठक (बीपीएम) बिंदु पर 14वीं कोर-कमांडर-स्तरीय बैठक हुई।^[72] 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद, चीनी उत्पादों के बहिष्कार के बारे में कुछ भारतीय अभियान शुरू किए गए।^{[73] [74]} आर्थिक मोर्चे पर कार्रवाई में चीनी कंपनियों के साथ कुछ अनुबंधों को रद्द करना और अतिरिक्त जांच करना शामिल था, और भारत में रणनीतिक बाजारों में चीनी कंपनियों के प्रवेश को रोकने के लिए भी आह्वान किया गया था।^{[75] [76] [77]} नवंबर 2020 तक, भारत सरकार ने 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें अलीबाबा, टेनसेंट, Baidu, सिना और बाइटडांस के स्वामित्व वाले ऐप्स शामिल थे।^[78]

चीन और भारत के बीच सीमा कई स्थानों पर विवादित है। "एलएसी के भारतीय संस्करण को दर्शाने वाला कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नक्शा नहीं है" और सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे भारत की आधिकारिक सीमा का एकमात्र प्रमाण हैं।^[79] एलएसी के चीनी संस्करण में ज्यादातर लद्दाख क्षेत्र पर दावे शामिल हैं, लेकिन चीन पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है।^[79]

चीन और भारत के बीच इससे पहले 1962 और 1967 में सीमा पर लड़ाई हुई थी, जिसमें चीन को पहले और बाद में भारत को जीत मिली थी।^{[80] [81]}

1980 के दशक से दोनों देशों के बीच इन सीमा मुद्दों को लेकर 50 से अधिक दौर की बातचीत हो चुकी है।^[82] 2010 और 2014 के बीच केवल 1 से 2 प्रतिशत सीमा घटनाओं को किसी भी प्रकार का मीडिया कवरेज मिला था।^{[82] [83]} 2019 में, भारत ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा 660 से अधिक एलएसी उल्लंघन और 108 हवाई उल्लंघन की सूचना दी, जो 2018 में घटनाओं की संख्या से काफी अधिक थी।^[84] झड़पों और गतिरोध के बावजूद, कोई घटना नहीं हुई सीमा पर दोनों देशों के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से गोलीबारी की खबरें आ रही थीं, क्योंकि दोनों पक्षों ने इस समझौते पर सहमति जताई थी कि बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा;^[85] हालांकि यह 7 सितंबर को बदल गया, जब चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गईं।^[50]

सितंबर 2014 में शी जिनपिंग की ^[86] नई दिल्ली यात्रा के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा प्रश्न पर चर्चा की और अपने समकक्ष से समाधान के लिए आग्रह किया। ^[87] 2014 में मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद से 2020 के गतिरोध तक, मोदी और शी ने 18 बार मुलाकात की, जिसमें शिखर सम्मेलन के मौके पर और चीन की पांच यात्राएं शामिल थीं। ^[88] हालांकि, 2017 में, चीन और भारत डोकलाम में एक बड़े गतिरोध में शामिल थे जो 73 दिनों तक चला था। ^[89] ^[90] 3 जनवरी 2018 को, केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में शी जिनपिंग ने पहला ट्रेनिंग मोबिलाइजेशन ऑर्डर जारी किया। यह पहली बार था कि सैन्य प्रशिक्षण निर्देश सीधे केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए गए थे। इसके बाद पीएलए बल आदेश के आधार पर प्रशिक्षण जुटा रहे हैं। ^[91]

पीएलए के एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल ने बताया कि, "... युद्ध की तैयारी में सुधार करना अब चीनी सेना के लिए एक रणनीतिक मिशन है ... चीन विदेशों में वास्तविक युद्ध के माध्यम से युद्ध क्षमता में सुधार के लिए अमेरिका के उपाय की नकल नहीं कर सकता क्योंकि हमारी राष्ट्रीय रक्षा नीति है आक्रामक के बजाय रक्षात्मक। इसलिए, चीन के लिए सैन्य प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।" ^[91] चीन ने तब से तिब्बती पठार में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। ^[92] चीन भारत के पड़ोसियों - नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ भी अपने पदचिह्न बढ़ा रहा है; इसलिए इस क्षेत्र में भारत का एकाधिकार होने के कारण, चीन अब दक्षिण एशिया में नई दिल्ली के प्रभाव को सीधी चुनौती दे रहा है। ^[93]

विचार-विमर्श

इन झड़पों के लिए कई कारणों का हवाला दिया गया है। अमेरिकी सीनेट के अल्पसंख्यक नेता मिच मैककोनेल और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वरिष्ठ साथी एशले टेलिस के अनुसार, इसका एक कारण चीन की क्षेत्र हथियाने की तकनीक है, जिसे 'सलामी स्लाइसिंग' भी कहा जाता है, जिसमें दुश्मन के क्षेत्र के छोटे हिस्सों पर अतिक्रमण शामिल है। समय की एक बड़ी अवधि में, ^[95] ^[96] जून 2020 के मध्य में, कोयुल - डेमचोक के चेरपरसन उर्गेन चोडन ने कहा कि लगातार भारतीय सरकारों (वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार सहित) ने दशकों तक सीमावर्ती क्षेत्रों की उपेक्षा की है और चीनी भूमि पर "आंखें मूंद लीं" हैं। क्षेत्र में कब्जा। उनके मुताबिक, भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा में नाकाम रहा है और 2020 में भी एलएसी पर भारत को जमीन गंवानी पड़ी है। ^[97] ^[98] अन्य स्थानीय लड़ाखी नेताओं ने भी क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा इसी तरह की घुसपैठ को स्वीकार किया। ^[99] इसके अलावा जून 2020 के मध्य में, अरुणाचल प्रदेश से भाजपा सांसद तापिर गाओ ने उत्तर-पूर्व भारत के अंदर भी नियमित चीनी गश्त की उपस्थिति को स्वीकार किया। ^[100]

एमआईटी के प्रोफेसर, टेलर फ्रैवेल ने कहा कि झड़पें लद्दाख में भारतीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चीन की प्रतिक्रिया थी, खासकर दारबुक-श्योक-डीबीओ रोड पर। उन्होंने कहा कि यह COVID-19 महामारी के बीच चीन के लिए ताकत का प्रदर्शन था, जिसने चीनी अर्थव्यवस्था और उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। ^[101] स्टिम्सन सेंटर के चीन विशेषज्ञ युन सन के अनुसार, चीन भारत के सड़क निर्माण को अपनी "क्षेत्रीय अखंडता" के लिए खतरा मानता है जिसे वह भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए त्याग नहीं करेगा। ^[102]

निर्वासित तिब्बती सरकार के अध्यक्ष लोबसांग सांगे ने कहा कि चीन चीन के भीतर आंतरिक समस्याओं और सीओवीआईडी -19 पर चीन पर डाले जा रहे अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण सीमा मुद्दे उठा रहा है। ^[103] ^[104] राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पूर्व सदस्य जयदेव रानाडे ने कहा कि क्षेत्र में चीन की वर्तमान आक्रामकता लद्दाख और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसे आसपास के क्षेत्रों में अपनी संपत्तियों और भविष्य की योजनाओं की रक्षा के लिए है। ^[105]

चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प러리 इंटरनेशनल रिलेशंस के वांग शिदा ने वर्तमान सीमा तनाव को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और 2019 में जम्मू और कश्मीर की स्थिति को बदलने के भारत के फैसले से जोड़ा। ^[63] हालांकि, प्रवीण साहनी वांग से सहमत थे, उन्होंने कहा कि एक संसदीय भाषण गृह मंत्री अमित शाह भी चीन को नाराज़ कर सकते थे। भाषण में, शाह ने घोषणा की थी कि अक्साई चिन, चीन द्वारा प्रशासित एक विवादित क्षेत्र, भारत प्रशासित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा था। ^[106] इसके अलावा, 2019 में जम्मू और कश्मीर के विभाजन ने भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्रियों को, हाल ही में मई 2020 में, यह दावा करने के लिए प्रेरित किया कि अब भारत के लिए गिलगित-बाल्टिस्तान को फिर से हासिल करना ही बाकी रह गया है। ^[107] भारतीय राजनयिक गौतम बंबावले भी इस बात से सहमत थे कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित नई दिल्ली के कदमों ने बीजिंग को परेशान किया है। ^[107]

अन्य विश्लेषकों ने झड़पों को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते गठबंधन से जोड़ा। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के दक्षिण एशिया विशेषज्ञ लियू जोंग्यी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि "भारत चीन को लक्षित करने वाली कई अमेरिकी योजनाओं में सक्रिय रहा है"। फेटफुल ट्रायंगल (अमेरिका, भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में एक किताब) की लेखिका तन्वी मदान ने कहा कि भारत ने सोचा कि यह अमेरिका के साथ अपने संबंधों को "सीमित" करने के लिए "बीजिंग से संकेत" था। ^[108] भारत के पूर्व राजनयिक फुंचोक स्टोबदान ने कहा कि "भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी छोटी शक्तियां, जिन्होंने अमेरिका के साथ गठबंधन किया है, चीन को अधिक आक्रामक देख रही हैं"। ^[109]

चीन में भारत के पूर्व राजदूत अशोक कांथा ने कहा कि ये झड़पें भारत-चीन सीमा और दक्षिण चीन सागर दोनों में बढ़ती चीनी आक्रामकता का हिस्सा थीं। ^[101] सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान के निदेशक राजा मोहन लिखते हैं कि चीन और भारत के बीच बढ़ता शक्ति असंतुलन विवाद का मुख्य कारण है, बाकी सब कुछ जैसे कि विवाद का

स्थान या भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, केवल विवरण मात्र हैं।^[110] इन झड़पों को कई लोगों ने तिब्बत की पांच उंगलियों की चीनी रणनीति से भी जोड़ा है।

अप्रैल 2020 के बाद से पीएलए की ग्राउंड फोर्स के पश्चिमी थिएटर कमांड, 4ठी (हाईलैंड) मोटराइज्ड इन्फैंट्री और 6वीं (हाईलैंड) मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री डिवीजनों के डिवीजनों ने मौजूदा तैनाती को मजबूत करते हुए पूर्वी लद्दाख में एलएसी की ओर इकाइयों को स्थानांतरित कर दिया। डिवीजन मई 2020 से फरवरी 2021 तक पूर्वी लद्दाख में रहे, जिसके बाद वे 8वें और 11वें मोटराइज्ड डिवीजनों के साथ घूमते रहे।^{[115] [116]} पीएलए वायु सेना और पीएलए रॉकेट फोर्स समर्थन में तैनात हैं।^[116]

गलवान के बाद, तीनों क्षेत्रों- उत्तरी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में चीन के खिलाफ भारत की तैनाती में समग्र वृद्धि हुई है।^[117] भारत द्वारा चीन की ओर निर्देशित पूर्व तैनाती में लेह में स्थित 14 कोर, सिक्किम में 17 कोर और 33 कोर, और पूर्वी क्षेत्र में 3 कोर और 4 कोर शामिल थे।^[118] इसमें कुछ परिवर्धन और परिवर्तन किए गए हैं, जैसे मैदानी इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए निर्धारित 14 डिवीजन को चीन के खिलाफ हिमाचल और उत्तराखंड में तैनाती के लिए एक पर्वतीय डिवीजन में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है।^[118] भारत के अर्धसैनिक बल जैसे कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को अधिकांश स्थानों पर सीमा के करीब तैनात किया गया है, सेना उनसे कुछ किलोमीटर पीछे है।^[119]

कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की जून 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन द्वारा भारत-चीन सीमा पर कई स्थानों पर जमीन पर कब्जा करने के एक साथ प्रयास किए गए हैं।^[120] पैंगोंग त्सो, कुगरांग घाटी ("हॉट स्पिंग्स" और "गोगरा" के रूप में संदर्भित), गलवान घाटी, देपसांग बुलगे क्षेत्र, गुरुंग हिल और लद्दाख में रेकिन ला में गतिरोध, झड़पें और अपराध हुए हैं; और सिक्किम में एक स्थान पर।^{[120] [121]} लद्दाख में तनाव कम करने की बातचीत के बीच, 29 जून 2020 को, चीन ने पहली बार यह दावा करके सीमा विवाद में एक नया मोर्चा खोल दिया कि सतेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान के ट्रेशिगांग के विवादित क्षेत्र में स्थित है। जिला।^{[122] [123]}

जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में, पीएलए द्वारा लद्दाख के अलावा अन्य स्थानों जैसे कि उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे, उत्तरी सिक्किम के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने और सैनिकों को जमा करने की खबरें सामने आईं।^[124] गलवान घाटी संघर्ष के बाद, भारत ने दक्षिण चीन सागर में एक युद्धपोत तैनात किया।^{[125] [126]} 2021 में रिपोर्ट की गई पहली सीमा झड़प 20 जनवरी को हुई थी, जिसे सिक्किम में मामूली सीमा झड़प के रूप में जाना जाता है।^[127]

परिणाम

5 मई को, पहला गतिरोध पैंगोंग त्सो के समुद्र तट पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के रूप में शुरू हुआ, जो भारत और तिब्बत, चीन के बीच साझा एक झील है, जिसके माध्यम से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) गुजरती है।^{[134] [135]} एक वीडियो में दोनों देशों के सैनिकों को एलएसी पर झड़प और पथराव करते हुए दिखाया गया है।^[136] 10/11 मई को एक और झड़प हुई।^[137] दोनों पक्षों के कई सैनिकों को चोटें आईं। भारतीय मीडिया ने बताया कि पैंगोंग त्सो में टकराव में लगभग 72 भारतीय सैनिक घायल हो गए, और कुछ को लेह, चंडी मंदिर और दिल्ली के अस्पतालों में ले जाना पड़ा।^[138] द डेली टेलीग्राफ और अन्य स्रोतों के अनुसार, चीन ने मई और जून 2020 के बीच भारतीय गश्त वाले क्षेत्र के 60 वर्ग किलोमीटर (23 वर्ग मील) पर कब्जा कर लिया।^{[139] [140] [141]} अगस्त के अंत तक यह बताया गया था कि, भारत की केंद्र सरकार को मिले खुफिया इनपुट के मुताबिक चीन ने इस इलाके की 65 वर्ग किलोमीटर (25 वर्ग मील) जमीन पर कब्जा कर लिया है।^[142]

27 जून तक, चीन ने पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों पर सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी थी, फिंगर 4 के पास अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी (अप्रैल में यथास्थिति के विपरीत), और यहां तक कि एक हेलीपैड का निर्माण भी शुरू कर दिया था। बंकर और पिलबॉक्स।^[143] प्लैनेट लेब्स द्वारा 12 से 26 जून के बीच की सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि चीनी सेना ने फिंगर 4 और 5 के बीच बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में वृद्धि की है, जिसमें तंबू, खाइयां, पानी के टैंक और कुछ छद्म संरचनाओं के साथ तैनात उपकरण और वाहन शामिल हैं। प्लैनेट लेब्स इमेजरी में फिंगर 4 और 5 के बीच झील के किनारे पर चीन के वर्तमान मानचित्र के साथ-साथ चीन के मंदारिन चीनी नाम झोंगगुओ के साथ खुदा हुआ इलाका भी दिखा।^{[144] [145]}

समुद्र तल से 13,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित पैंगोंग झील पर गश्त के लिए दोनों देशों के पास कई उच्च शक्ति वाली नावें हैं। जबकि भारतीय सेना के पास पहले से ही कई नाव गश्ती दल तैनात थे, जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना को झील पर चीनी प्रकार 928 बी जहाजों की उपस्थिति से मेल खाने के लिए बुलाया गया था।^{[146] [147]} सितंबर के पहले सप्ताह में, एक सरकारी अधिकारी के हवाले से भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर दोनों पक्षों द्वारा "चेतावनी शॉट" के रूप में "100 से 200 गोलियाँ" चलाई गईं।^{[148] [149]}

29-30 अगस्त को, झड़पें चुशुल के लद्दाखी गांव के पास पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट तक फैल गईं।^[150] भारतीय सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि पीएलए ने 29/30 अगस्त की रात को पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर उत्तेजक सैन्य गतिविधियां की थीं और उन्हें भारतीय प्रतिक्रिया से पहले ही मौका मिल गया था, जो तेजी से ऊंचे इलाके पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। बिना किसी हिंसा के एक रक्षात्मक कदम।^{[156] [157] [158]} पीएलए द्वारा भविष्य में किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में अपने सैनिकों को तैनात कर दिया।^[159] चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने पीएलए द्वारा भारतीय क्षेत्र में किसी भी घुसपैठ से इनकार किया। वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता झांग शुइली ने भारतीय सेना पर उकसावे और चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।^[160]

मुद्रों को सुलझाने के लिए ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग बुलाई गई।^[161] 3 सितंबर 2020 तक, भारतीय मीडिया ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर कई ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। उल्लिखित ऊंचाइयों में रेजांग ला, रेकिन ला, ब्लैक टॉप, हनान, हेलमेट, गुरुंग हिल, गोरखा हिल और मगर हिल शामिल हैं।^[162] इनमें से कुछ ऊंचाइयां एलएसी के ग्रे जोन में हैं और चीनी शिविरों पर नजर रखती हैं।^[163]

4 सितंबर 2020 को मॉस्को में चीन और भारत के बीच उच्च स्तरीय बैठक के दौरान चुशुल सेक्टर में रेचिन ला से आक्रामक रुख की सूचना मिली थी। पीएलए सैनिकों को ब्लैक टॉप पर एंटी-एयरक्राफ्ट गन ले जाते हुए भी देखा गया।^[71] भारतीय रिपोर्टों के अनुसार, 7 सितंबर 2020 को शाम लगभग 6:15 बजे पीएलए सैनिकों ने मुखपारी में भारतीय ठिकानों के पास आने की कोशिश की।^[164] पीएलए सैनिकों की भाले, छुरी और राइफलें ले जाने की तस्वीरें जारी की गईं; यह चीनी सैनिकों द्वारा ऐसे हथियारों का उपयोग करने का सार्वजनिक रूप से जारी किया गया पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य था।^[165] यहां की ऊंचाइयों पर नियंत्रण रखने वाले भारतीय सैनिकों ने पीएलए सैनिकों को आने से रोकने के लिए फ्लडलाइट और मेगाफोन का इस्तेमाल किया। भारतीय रिपोर्टों में कहा गया है कि तभी पीएलए सैनिकों ने 10-15 राउंड फायरिंग की। हालांकि पीएलए के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं। पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि भारतीय सेना "शेनपाओ पर्वत क्षेत्र" में प्रवेश करने के लिए एलएसी पार कर गई थी।^{[166] [167] [168]}

8 सितंबर को भारत और चीन दोनों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाने के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया।^{[169] [170] [171] [172]} 45 वर्षों में यह पहली बार है, 1975 के बाद जब चीनियों ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में असम राइफल्स के गश्ती दल पर गोलीबारी की, भारत और चीन के बीच गोलीबारी हुई है।^[51] भारतीय मीडिया ने यह भी बताया कि पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर यथास्थिति को बदलने से रोकने के लिए भारतीय सैनिकों ने 30 अगस्त को पीएलए पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं।^{[52] [173]} भारतीय सैनिकों ने चौकियों के चारों ओर कंटीले तारों की बाधाएं खड़ी कर दी हैं।^[174]

भारत सरकार के सूत्रों ने हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप सुविधाओं पर कब्जा करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए "कोई भी प्रक्षेप पथ" संभव है।^[175]

भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 मई को सिक्किम के नाकु ला के मुगुथांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई थी। इस घटना में कई सैनिकों के बीच विवाद हुआ, विरोधी पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर भी फेंके।^{[89] [176]} दोनों पक्षों के कुछ सैनिक घायल हो गए।^{[33] [177]} भारतीय सेना की पूर्वी कमान के एक प्रवक्ता ने कहा कि मामला "स्थानीय स्तर पर 'बातचीत और बातचीत' के बाद सुलझा लिया गया है" और "सीमा रक्षकों के बीच अस्थायी और छोटी अवधि की झड़पें होती हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीमाएं हल नहीं होती हैं। सैनिक आमतौर पर पारस्परिक रूप से स्थापित प्रोटोकॉल का उपयोग करके ऐसे मुद्दों को हल करते हैं।^{[89] [90]} चीन ने घटना के बारे में विवरण साझा नहीं किया, और चीनी रक्षा मंत्रालय ने घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की।^[178] हालांकि, विदेश मंत्रालय ने कहा कि "चीनी सैनिकों ने हमेशा सीमा पर शांति बनाए रखी है"।^[178]

21 मई को, इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि चीनी सैनिक गलवान नदी घाटी में भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और (निर्विवाद) भारतीय क्षेत्र के भीतर भारत द्वारा सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई थी। निर्माणाधीन सड़क दरबुक-श्योक-डीबीओ रोड (डीएसडीबीओ) की एक शाखा है जो गलवान घाटी की ओर जाती है।^[179] रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि "चीनियों ने क्षेत्र में 70-80 तंबू गाड़ दिए और फिर सैनिकों, भारी वाहनों और निगरानी उपकरणों के साथ क्षेत्र को मजबूत किया।"^[180] 24 मई को, एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी सैनिकों ने तीन अलग-अलग स्थानों पर भारत पर आक्रमण किया: हॉट स्प्रिंग्स, पेट्रोल प्वाइंट 14, और पेट्रोल प्वाइंट 15।^{[45] [46]}

इनमें से प्रत्येक स्थान पर, लगभग 800-1,000 चीनी सैनिक कथित तौर पर एलएसी पार कर गए और सीमा से लगभग 2-3 किमी (1-2 मील) दूर एक स्थान पर बस गए, तंबू गाड़ दिए और भारी वाहन और निगरानी उपकरण तैनात कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने भी क्षेत्र में सेना तैनात की और उन्हें चीनी सैनिकों से 300-500 मीटर (984-1,640 फीट) दूर तैनात किया।^{[45] [46]} यूरेशियन टाइम्स ने कहा कि चीनी सेना के पास "सैन्य शैली के बंकर, नई स्थायी संरचनाएं, सैन्य ट्रक और सड़क निर्माण उपकरण सहित एक विशाल निर्माण है"।^[181] 30 मई को, अजय शुक्ला ने बताया कि हजारों चीनी सैनिक "अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे," और पैंगोंग त्सो में 18 बंदूकें और गलवान घाटी में लगभग 12 बंदूकें थीं। भारतीय सैनिकों ने पीएलए को डीएसडीबीओ रोड की ओर आगे बढ़ने से रोकने के लिए पोजीशन ले ली थी।^[182]

27 मई 2020 को, भारत में चीनी राजदूत के साथ-साथ चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि समग्र स्थिति स्थिर थी।^[183] हालांकि, समाचार रिपोर्टों में कहा गया कि हजारों चीनी सैनिक लद्दाख में विवादित क्षेत्रों में जा रहे थे। इस कदम ने भारत को और अधिक सैनिक तैनात करने के लिए प्रेरित किया।^{[184] [185]} गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स में चीनी बुनियादी ढांचे के विकास की भी सूचना मिली थी। सेटेलाइट इमेजरी में ट्रैक से पता चलता है कि पीएलए सैनिक यहां भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं।^[186]

15 जून को, गश्त बिंदु 14^{प्र}, भारतीय और चीनी सैनिक गलवान घाटी में एक पहाड़ी क्षेत्र के एक खड़ी हिस्से में छह घंटे तक भिड़ते रहे। घटना का तात्कालिक कारण अज्ञात है, इसके बाद दोनों पक्षों ने विरोधाभासी आधिकारिक बयान जारी किए।^{[187] [188]} बीजिंग ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने पहले चीनी सैनिकों पर हमला किया था,^[189] जबकि 18 जून को द हिंदू ने भारत के विदेश मंत्रालय के एक "वरिष्ठ सरकारी अधिकारी" के हवाले से कहा कि उनके सैनिकों पर क्षतिग्रस्त नालों में घात लगाकर हमला किया गया था। रिहा किया जा रहा है और चीनी सैनिकों द्वारा पत्थर फेंके जा रहे हैं।^[190] बयान में कहा गया है कि

यह तब हुआ जब वे एक विवादित क्षेत्र में गश्त कर रहे थे जहां कर्नल संतोष बाबू ने दो दिन पहले एक चीनी तम्बू को नष्ट कर दिया था।^[190]

जबकि सैनिक आग्रेयास्त्र रखते हैं, तनाव बढ़ने की संभावना को कम करने के लिए बनाई गई दशकों की परंपरा के कारण, समझौतों में आग्रेयास्त्रों के उपयोग की अनुमति नहीं है, लेकिन चीनी पक्ष के पास लोहे की छड़ें, कांटेदार तारों में लिपटे डंडे और डंडे और कीलों से जड़े हुए डंडे होने की सूचना मिली थी।^{[191][192]} आमने-सामने की लड़ाई शुरू हो गई, और भारतीय सैनिकों ने लगभग 3.2 किलोमीटर (2 मील) दूर एक चौकी से सुदृढीकरण बुलाया। आखिरकार, 600 से अधिक लोग पथरों, डंडों, लोहे की छड़ों और अन्य अस्थायी हथियारों का उपयोग करके युद्ध में लगे हुए थे। लगभग पूर्ण अंधकार में हुई लड़ाई छह घंटे तक चली।^[193] भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2020 वर्ष के अंत की समीक्षा में कहा कि चीन ने "अपरंपरागत हथियारों" का इस्तेमाल किया।^[194]

लड़ाई के परिणामस्वरूप 20 भारतीय सैनिक मारे गए, जिनमें 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू^{[195][196]} और जूनियर कमीशंड ऑफिसर नुदुराम सोरेन वीआरसी^{[197][एम]} शामिल थे, जबकि तीन भारतीय सैनिकों की मौत पर ही मौत हो गई, अन्य की मौत हो गई। बाद में चोटों और हाइपोथर्मिया के कारण।^[199] मारे गए अधिकांश सैनिकों की मौत पैर फिसलने या पहाड़ी से धक्का दिए जाने के कारण हुई।^[193] झड़प तेज़ बहती गलवान नदी के पास हुई और दोनों पक्षों के कुछ सैनिक एक नाले में गिर गए और मारे गए या घायल हो गए।^[199] बाद में शव श्योक नदी से बरामद किए गए।^[196] कई भारतीय समाचार आउटलेट्स ने कहा कि 4 अधिकारियों सहित कम से कम 10 भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया गया और फिर 18 जून को चीनी सेना द्वारा रिहा कर दिया गया।^[25]

जनरल वीके सिंह के मुताबिक, अपुष्ट संख्या में चीनी सैनिकों को भी पकड़ लिया गया और बाद में भारत ने रिहा कर दिया।^[38] कुछ भारतीय सैनिकों को भी क्षण भर के लिए बंदी बना लिया गया था।^[199] भारतीय मीडिया सूत्रों के अनुसार, इस हमले में 43 चीनी लोग हताहत हुए।^{[47][200]} सूत्रों के आधार पर मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चीनी पक्ष ने घटना के बाद तनाव कम करने की बैठक स्वीकार की; हमले में एक चीनी कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया।^[48] चीनी रक्षा मंत्रालय ने चीनी हताहतों की संख्या की पुष्टि की लेकिन संख्या साझा करने से इनकार कर दिया।^[201] चीनी इंटरनेट पर रिपोर्ट सामने आई कि 16 जून को पांच चीनी सैनिक मारे गए,^{[202][203]} लेकिन बाद में रिपोर्ट को चीनी सरकार द्वारा सेंसर कर दिया गया।^[204] 22 जून को, जब चीन से हताहतों की संख्या के बारे में एक भारतीय मंत्री के दावे के बारे में पूछा गया, तो चीन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।^[205]

दो दिन बाद 24 जून को एक चीनी प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी और भारतीय मंत्री की टिप्पणी को 'गलत सूचना' कहा।^[206] अमेरिकी खुफिया ने बताया कि पीएलए को 35 हताहतों का सामना करना पड़ा।^[एम] भारतीय मीडिया ने बताया कि 17 जून को 10 भारतीय सैनिकों को चीनी हिरासत से रिहा कर दिया गया, जिनमें चार अधिकारी भी शामिल थे।^{[25][208]} रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारतीय सेना और चीनी विदेश मंत्रालय दोनों ने इस बात से इनकार किया है कि किसी भी भारतीय कर्मियों को हिरासत में लिया गया था।^[209] 19 फरवरी 2021 को, चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने कहा कि उसके चार सैनिकों को जून 2020 में गलवान में भारत के साथ झड़प के दौरान उनके कार्यों के लिए मरणोपरान्त सम्मानित किया गया।^[210]

16 जून को, पीएलए के पश्चिमी कमान के प्रवक्ता, चीनी कर्नल झांग शुइली ने कहा कि भारतीय सेना ने द्विपक्षीय आम सहमति का उल्लंघन किया, जिससे "भयंकर शारीरिक टकराव और हताहत" हुए,^[211] और "गलवान घाटी क्षेत्र पर संप्रभुता हमेशा उनकी रही है।" चीन।^{[196][212][213]} 18 जून को, भारत के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया जिसमें कहा गया कि चीन ने "यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश की थी" और हिंसा "पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध" थी।^{[214][215]} उसी दिन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के सहायक सचिव ने कहा कि चीनी पीएलए ने भारत और चीन के बीच "विवादित क्षेत्र" पर "आक्रमण" किया था।^[216]

हालाँकि, 19 जून को, प्रधान मंत्री मोदी ने भारत सरकार के पिछले कई बयानों का खंडन करते हुए घोषणा की कि "न तो [चीन] ने हमारी सीमा में घुसपैठ की है, न ही उन्होंने किसी पोस्ट पर कब्जा किया है।"^{[187][217]} बाद में प्रधान मंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय प्रधान मंत्री 16 बिहार रेजिमेंट की बहादुरी का संकेत देना चाहते थे जिन्होंने चीनी पक्ष के प्रयास को विफल कर दिया था।^{[218][219]} 22 जून को, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आकलन किया है कि चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख जनरल झाओ जोंगकी ने झड़प को मंजूरी दी थी।^[220] गलवान की घटना के बाद, भारतीय सेना ने सीमा पर सैनिकों को हल्के दंगा गियर के साथ-साथ नुकीले क्लबों से लैस करने का निर्णय लिया।^{[221][222]}

20 जून को, भारत ने LAC पर भारतीय सैनिकों के लिए आग्रेयास्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध हटा दिया।^[223] ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक नीति संस्थान द्वारा विश्लेषण की गई उपग्रह छवियों से पता चलता है कि चीन ने 15 जून की झड़प के बाद से गलवान घाटी में निर्माण बढ़ा दिया है।^[70] जिस चीनी चौकी को 15 जून को भारतीय सैनिकों ने नष्ट कर दिया था, उसे आकार में विस्तार और अधिक सैन्य आवाजाही के साथ 22 जून तक पुनर्निर्माण किया गया था। घाटी में भारतीय और चीनी दोनों सेनाओं द्वारा अन्य नई रक्षात्मक स्थितियाँ भी बनाई गई हैं।^[224]

देपसांग में भारत-चीन तनाव मई 2020 के गतिरोध से कुछ महीने पहले शुरू हुआ था।^[225] चीनी उपस्थिति, एलएसी की भारतीय धारणा के अंदर 18 किमी (11 मील), देपसांग मैदान के दक्षिण में राकी नाला पर वाई-जंक्शन या बॉटलनेक के पास,^[ओ] 25 जून 2020 को भारतीय मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई थी। रिपोर्ट सैनिकों, भारी वाहनों और सैन्य उपकरणों की आवाजाही का वर्णन किया गया। चीनी दावे की रेखाएँ बॉटलनेक से 5 किमी आगे पश्चिम में हैं।^[226] भारतीय गश्ती बिंदु (पीपी) 10, 11, 11ए, 12 को मार्च-

अप्रैल 2020 से वाई-जंक्शन पर पीएलए आंदोलन और निर्माण द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। [227] [228] 31 अगस्त 2020 को खुफिया इनपुट ने चीनियों को चौंका दिया है। लगभग 900 वर्ग किलोमीटर (350 वर्ग मील) एलएसी के बारे में भारत की धारणा के भीतर क्षेत्र का नियंत्रण। [142] [229]

चीन और भारत दोनों ही रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सीमाओं पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचा शामिल है। [230] ब्रह्मपुत्र नदी पर और अधिक बांध निर्माण की चीनी घोषणाओं के बाद, भारत ने कहा कि उसे चीनी बांध निर्माण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए नदी के किनारे एक बांध बनाने की आवश्यकता होगी। [231] [232] [233] यह निर्माण 2020 और 2021 तक जारी रहा है। [234]

गतिरोध के बीच, भारत ने भारतीय सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में मदद के लिए लगभग 12,000 अतिरिक्त श्रमिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। [57] [58] लगभग 8,000 कर्मचारी लद्दाख में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की बुनियादी ढांचा परियोजना, प्रोजेक्ट विजयक में मदद करेंगे, जबकि कुछ श्रमिकों को आसपास के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आवंटित किया जाएगा। [235] श्रमिक 15 जून से 5 जुलाई के बीच लद्दाख पहुंचेंगे। [59] 1,600 से अधिक श्रमिकों के साथ पहली ट्रेन 14 जून 2020 को झारखंड से उधमपुर के लिए रवाना हुई, और वहां से श्रमिक चीन-भारत सीमा पर बीआरओ की सहायता के लिए चले गए। [59] [236] डीएस-डीबीओ रोड को पूरा करने के अलावा श्रमिक अन्य सीमा सड़कों के निर्माण में भी बीआरओ की सहायता करेंगे। [237]

जून से शुरू होकर, सरकार ने भारत-चीन सीमा पर काम करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन में 170% तक की वृद्धि की घोषणा की, जिसमें लद्दाख में कर्मचारियों के वेतन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। [238] विशेषज्ञों का कहना है कि सीमा पर भारतीय बुनियादी ढांचे का विकास गतिरोध के कारणों में से एक था। [60] लाइवमिंट की रिपोर्ट है "हालांकि इस तरह की परिसंपत्ति निर्माण से भारत की रणनीतिक पूंजी में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन यह उसी तरह से अपनी मानव पूंजी को आगे नहीं बढ़ा रही है।" [239] भारत ने एलएसी पर निगरानी उपकरण भी स्थापित किए हैं। [240] अक्टूबर 2021 में, नई सीमा चौकियों के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी गई, जिसमें वे स्थान भी शामिल हैं जहां चीन के साथ तनाव बढ़ गया है। [241] 2021 के अंत में, भारत ने कई सीमा सड़कों और पुलों का उद्घाटन किया, जिसमें चिसुमले-डेमचोक सड़क का उमलिंग ला खंड भी शामिल है। [242]

गतिरोध के दौरान चीन ने एलएसी के पास बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखा। [243] बुनियादी ढांचे में सड़कें, पुल, हेलीपैड और शिविर जैसे अन्य सैन्य बुनियादी ढांचे शामिल हैं। पैंगोंग त्सो और गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में टकराव वाले स्थानों पर अपने अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है। [244] पैंगोंग त्सो में दो नए मरीना भी बनाए गए हैं। [150] चीन ने एलएसी पर कैमरे, मोशन सेंसर और अन्य निगरानी उपकरण स्थापित किए हैं। [245] झिंजियांग और तिब्बत में एयरबेस को और अधिक विकसित किया जा रहा है; इसमें होटन, काशगर, गर्गुसा, ल्हासा-गोंगगर और शिगात्से के एयरबेस शामिल हैं। [244]

कैलाश-मानसरोवर में लिपुलेख दर्रे के पास चीन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट का निर्माण कर रहा है। [246] [247] चीन एलएसी पर अपने सैनिकों के लिए 5जी नेटवर्क भी विकसित कर रहा है। [248] [249] चीन द्वारा सीमा पर सैटेलाइट जैमर तैनात करने की खबरें भी सामने आईं। [250] जुलाई में, स्ट्रेटफोर ने बताया कि चीनी सेना ने भारतीय सीमा पर 26 नए अस्थायी बैरक और 22 नए अड्डे बनाए हैं; "स्थायी और अर्ध-स्थायी पदों का मिश्रण।" [251] [252] सितंबर में, स्ट्रेटफोर ने बताया कि गतिरोध की शुरुआत के बाद से, चार नए हेलीपोर्ट का निर्माण शुरू हो गया है। सिम टैक की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालय में चीन का यह निर्माण दक्षिण चीन सागर में चीनी रणनीति के समान है, एक ऐसी रणनीति जो चीन के दावों का विरोध करने की कोशिश करने वालों के लिए लागत में काफी वृद्धि करती है। [253] [254]

नवंबर में, चीन ने कथित तौर पर भूटान के क्षेत्र में 2 किमी अंदर और 2017 डोकलाम गतिरोध स्थल से 9 किमी दूर पंगडा गांव का निर्माण किया, [255] जिस पर भारत में भूटानी राजदूत ने जवाब दिया, "भूटान के अंदर कोई चीनी गांव नहीं है।" [256] [257] [258] 2017 स्थल से 7 किमी दूर नए चीनी गोला बारूद बंकरों की भी सूचना मिली थी। [259] कुछ सप्ताह बाद, रिपोर्टें सामने आईं कि चीन ने बुम ला दर्रे के पास तीन गांवों का निर्माण किया है। कथित तौर पर चीनी क्षेत्र के भीतर गांवों का निर्माण किया जा रहा था, जबकि पूर्वी लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिक आमने-सामने थे। [260] इसके बाद जनवरी 2021 में ऊपरी सुबनसिरी जिले में सीमा के पास विवादित क्षेत्र में एक और गांव के निर्माण की रिपोर्ट आई। [261] [262] नवंबर 2021 में अरुणाचल के शि योमी जिले में एक और नए चीनी एन्क्लेव (कथित तौर पर) की सूचना मिली थी। [263]

असफल कूटनीतिक वार्ता और रुकी हुई सैन्य वापसी और तनाव कम करने की प्रक्रिया के बाद, चीन और भारत ने पूरे सर्दियों में लद्दाख में निरंतर तैनाती बनाए रखने के लिए खुद को तैयार किया। [270] [271] [272] [273] अक्सई चिन और लद्दाख के कुछ हिस्सों में तापमान, जो एक उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान है, -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जहां क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी होती है, वहीं पूर्वी लद्दाख में 60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। पैंगोंग त्सो में श्योक नदी जम गई है, पाइपों में पानी भी जम गया है। [274]

भारतीय पक्ष की रसद आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा ईंधन, तेल और स्नेहक (एफओएल) के रूप में है। तेल का उपयोग बुखारी जलाने और खाना पकाने के साथ-साथ पीने के पानी के लिए और हीटिंग सिस्टम वाले बैरकों के लिए बर्फ पिघलाने के लिए किया जाता है। आर्कटिक टेंट और सर्दियों के कपड़ों का स्टॉक कर लिया गया है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को 22 प्रकार के चावल, दालें और गेहूं, 65 आवश्यक खाद्य पदार्थ, सब्जियों जैसे नाशवान खाद्य पदार्थों सहित प्रावधानों के माध्यम से पूरा किया जाता है; और 18,000 फीट (5,500 मीटर) और उससे ऊपर की तैनाती के लिए उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ। एक अकेले

सैनिक को सर्दियों तक रहने के लिए लगभग 800 किलोग्राम भोजन की आवश्यकता होती है। हथियार और गोला बारूद जमा कर लिया गया है।^{[274] [275] [276]}

लद्दाख में स्थानीय संसाधन सीमित हैं, इसलिए सब कुछ मैदानी इलाकों से आता है।^[277] अतिरिक्त इंजीनियरिंग बलों को सैनिकों के लिए अतिरिक्त बैरक उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है;^[278] नवंबर के मध्य तक यह बताया गया कि सेना ने लद्दाख में "आवास सुविधाओं" का निर्माण पूरा कर लिया है।^[279] पूर्व सेना उपप्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल जेपी सिंह के अनुसार, एलएसी पर शीतकालीन तैनाती नए बुनियादी ढांचे के निर्माण, अतिरिक्त ट्रक और विमान की आवाजाही जैसे आवर्ती खर्चों और ऑफ-द-खरीद के कारण भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएगी। शैलफ शीतकालीन उपकरण; बदले में आधुनिकीकरण योजनाओं जैसे अन्य खर्चों पर असर पड़ रहा है।^{[आर] [269] [271]}

गतिरोध के बीच, भारत ने क्राड में भागीदारों - जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैन्य रसद साझाकरण समझौते को पूरा किया।^[283] डीआरडीओ ने लद्दाख में सैनिकों के लिए कई उत्पाद विकसित किए हैं जैसे हिम तपाक नामक एक नई बुहकारी।^[284] आईटीबीपी के लिए सीमा चौकियों के निर्माण में कई वर्षों की काफी देरी हुई है।^[285]

पीपुल्स डेली ने बताया कि पीएलए सर्दियों के लिए नए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, जैसे प्री-फैब्रिकेटेड आश्रय, और फ्रंटलाइन सैनिकों को गर्म भोजन पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करके अभ्यास कर रहा है।^[286] चीन पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में सैन्य रसद सुविधाएं स्थापित करने की भी मांग कर रहा है।^[287]

भारतीय सेना के सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्टें उंचाई और ठंड के कारण दैनिक सेना की संख्या कम होने की ओर इशारा करती हैं।^[288] यह क्षरण "अपेक्षित अनुपात के भीतर" है और जो ठीक हो जाते हैं उन्हें पुनः तैनात कर दिया जाता है। चीनी पक्ष को भी ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ता है।^[288] टिप्पणीकारों का कहना है कि यह संघर्ष का युद्ध बनता जा रहा है या बन चुका है;^[289] इसमें स्टिम्सन सेंटर के चीन विशेषज्ञ युन सन,^[290] और जेएनयू में चीनी अध्ययन के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली शामिल हैं।^[291] भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) जैसे अन्य सीमा बलों को भी संघर्ष संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।^[292]

2020 में वृद्धि के बाद, साइबर हमलों की रिपोर्ट में वृद्धि हुई।^{[293] [294] [295]} महाराष्ट्र साइबर विभाग को संदेह है कि 13 अक्टूबर 2020 को मुंबई में गंभीर ब्लैकआउट एक मैलवेयर हमले के कारण हुआ था।^[296] साइबर सिक्योरिटी फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर के फरवरी 2021 के एक अध्ययन में पाया गया कि 2020 में झड़पों के बाद चीनी मैलवेयर भारतीय बिजली आपूर्ति नियंत्रण प्रणालियों में प्रवाहित हुआ, हालांकि इसने मैलवेयर और मुंबई बिजली आउटेज के बीच एक लिंक को मान्य नहीं किया।^[297] कम से कम 12 सरकारी संगठनों, मुख्य रूप से बिजली उपयोगिताओं पर हमला होने की सूचना मिली थी।^[298]

आशय

पहली हाथापाई होने के बाद, 5-6 मई 2020 को पैंगोंग त्सो में, भारत के विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने भारत में चीनी राजदूत सन वेइदोंग को बुलाया।^[300] फिर, अजीत डोभाल ने कथित तौर पर एक शीर्ष चीनी राजनयिक यांग जिएची से बात की।^[300] 28 मई को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विदेश मंत्रालय के भारतीय प्रवक्ता, अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सीमा विवादों को कूटनीतिक रूप से हल करने के लिए पर्याप्त द्विपक्षीय तंत्र थे।^{[301] [64]} (हालांकि, कुछ आलोचकों का कहना है कि ये समझौते "गहराई से त्रुटिपूर्ण" हैं।^[302]) बॉर्डर पर्सनल मीटिंग (बीपीएम) बिंदुओं पर मई-जून में सैन्य वार्ता के दौर हुए थे। पहले कर्नलों के बीच, फिर ब्रिगेडियरों के बीच और 2 जून को मेजर जनरलों के बीच तीन से अधिक राउंड हुए।^{[68] [303]}

ये सभी वार्ताएं असफल रहीं। कुछ भारतीय सैन्य सूत्रों ने कहा कि भारत अभी भी चीन की मांगों को लेकर स्पष्ट नहीं है। सूत्रों ने कहा, "जब कोई किसी प्रक्रिया को रोकना चाहता है, तो वह बेतुकी मांगें करता है ... उन्होंने जानबूझकर कुछ अनुचित मांगें की हैं।"^[68] 6 जून को, कमांडरों की वार्ता चुशुल - मोल्डो बीपीएम में हुई। वार्ता में लेह मुख्यालय वाली XIV कोर के भारतीय कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और तिब्बत सैन्य जिले (दक्षिण शिनजियांग सैन्य क्षेत्र) के चीनी कमांडर मेजर जनरल लियू लिन शामिल थे।^[304]

17 जून 2020 को, प्रधान मंत्री मोदी ने गलवान झड़प के संबंध में राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें भारतीय सैनिकों की मौत पर चीन को कड़ा संदेश दिया गया।^{[305] [306]} चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के एस जयशंकर के बीच सीमा विवाद शुरू होने के बाद पहला संचार भी गलवान झड़प के बाद हुआ।^[305] जयशंकर ने गलवान में चीनी कार्रवाई को "पूर्व नियोजित और नियोजित" बताया।^[305] 20 जून को, चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट ने गलवान झड़प पर भारतीय प्रधान मंत्री की टिप्पणी को हटा दिया,^[307] जिसे चीन में भारतीय दूतावास द्वारा अपलोड किया गया था। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान भी हटा दिए गए। वीचैट ने कहा कि उसने भाषण और बयानों को हटा दिया क्योंकि उन्होंने राज्य के रहस्यों को उजागर किया और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला।^[308]

घटना पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान भी वीबो से हटा दिया गया। यह देखने पर कि पेज ने कहा कि सामग्री लेखक द्वारा हटा दी गई थी, चीन में भारतीय दूतावास ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि पोस्ट उनके द्वारा नहीं हटाया गया था, और चीनी भाषा में बयान का एक स्क्रीनशॉट फिर से प्रकाशित किया।^{[309] [310]} 1 जुलाई को, प्रधान मंत्री मोदी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो छोड़ दिया।^{[311] [312]} 3 जुलाई को, लद्दाख में सैन्य चौकियों के औचक दौरे के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी ने एक भाषण में कहा कि "विस्तारवाद का युग" समाप्त हो गया है और इतिहास से पता चला है कि "विस्तारवादी ताकतें या तो हार गई हैं या समाप्त हो गई हैं।" वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया"; मीडिया ने नोट किया कि यह बीजिंग के संदर्भ में था।^[313]

कमांडरों की बैठक का दूसरा दौर 22 जून को था। 11 घंटे की बैठक में कमांडरों ने डिसएंगेजमेंट की रूपरेखा तैयार की। 24 जून को, WMCC की आभासी बैठक के दौरान दोनों पक्षों द्वारा इस विघटन को कूटनीतिक रूप से स्वीकार किया गया था।^[70] चीनी प्रवक्ता, झाओ लिजियन ने कहा कि भारत "चीन के अनुरोध के अनुसार सहमत हो गया और गलवान घाटी में अपने सीमा पार कर्मियों को वापस ले लिया और क्रॉसिंग सुविधाओं को नष्ट कर दिया"।^{[70] [338]}

कमांडरों की तीसरे दौर की वार्ता 30 जून को हुई;^{[315] [316]} भारत ने पैगोंग त्सो, गलवान घाटी और डेपसांग मैदानों सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की वापसी और अप्रैल में यथास्थिति की बहाली की अपनी मांग दोहराई, जबकि चीन ने इस क्षेत्र में सैन्य निर्माण पर जोर दिया। कम किया जाना चाहिए।^[339] वार्ता के बाद, यह बताया गया कि चीनी वाहनों को गलवान टकराव बिंदु के साथ-साथ हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा से पीछे हटते देखा गया था।^[340]

पूर्ण विघटन के पहले असफल प्रयासों के बाद, 5 जुलाई को विशेष प्रतिनिधियों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री, वांग यी के बीच एक चर्चा हुई, जहाँ यह निर्णय लिया गया कि भारतीय और चीनी दोनों सैनिक पीछे हटेंगे। गलवान घाटी में 15 जून की झड़प स्थल, गश्त बिंदु पीपी 14 से 1.8 किमी दूर।^[341] यह बताया गया कि बफर जोन बनाने के लिए दोनों सैनिक पीपी 14 से लगभग 1.5 से 2 किमी पीछे चले गए, जो अगले 30 दिनों के लिए उनके लिए पैदल गश्त की सीमा से बाहर होगा। हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में सैनिकों की संख्या कम होने के साथ ही चीनी सेना पूरी तरह से संघर्ष स्थल से बाहर चली गई।^{[342] [343]} चीनी सैनिक पैगोंग त्सो से पीछे नहीं हटे, जहां वे भारतीय गश्त क्षेत्र में 8 किमी अंदर तक घुस आए थे।^{[344] [345]}

25 जुलाई को, भारतीय मीडिया ने गलवान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में सैनिकों की वापसी पूरी होने की सूचना दी।^{[346] [53]} 30 जुलाई को, चीनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि धीरे-धीरे सैनिकों की वापसी और तनाव कम हो रहा है; भारत ने चीन को बताया कि सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है,^[347] भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा कि "अब दो सप्ताह से अधिक समय से जमीन पर कोई सकारात्मक हलचल नहीं हुई है" और गोगरा और पैगोंग त्सो में सैनिकों की वापसी बाकी है।^{[348] [349]}

30 जुलाई को, चीनी राजदूत सन वेइदोंग ने दावा किया कि एलएसी को स्पष्ट करने की प्रक्रिया जारी नहीं रह सकती क्योंकि एलएसी के एकतरफा परिसीमन से अधिक विवाद होते हैं।^[350] कोर-कमांडर वार्ता का चौथा दौर 14 जुलाई को हुआ,^[317] जबकि पांचवें दौर की वार्ता 2 अगस्त को हुई।^[351] 24 जुलाई को दोनों देशों के बीच सैनिकों की वापसी के संबंध में राजनयिक वार्ता हुई।^[352] पांचवें दौर की वार्ता के बाद, चीन अध्ययन समूह ने बैठक की और पैगोंग त्सो में चीन के "पारस्परिक और समान" विघटन प्रस्ताव को अस्वीकार्य पाया।^{[353] [354]}

सीमा पर तनाव के 100वें दिन द वीक ने नई दिल्ली में सचिवालय भवन स्थित एक रक्षा अधिकारी के बयान की सूचना दी, "भारतीय सैन्य योजनाकारों का मानना है कि चीजें उनके नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। अब, केवल राजनीतिक हस्तक्षेप ही इस मुद्दे को हल कर सकता है।" सैन्य पक्ष ने बार-बार मैराथन चर्चा करके काफी कुछ किया है।"^[67] 27 अगस्त को, भारत के पूर्व विदेश सचिव, श्याम सरन ने 1987 में सोमदोरोंग चू का उदाहरण देते हुए कहा, "भारत को धैर्य रखने की जरूरत है ... जिसे हल करने में सात साल लग गए"।^[355]

चीनी जनरल वेई फेंगे और उनके भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह ने 4 सितंबर को माँस्को में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के मौके पर बातचीत की।^[71] 10 सितंबर को चीन और भारत के विदेश मामलों के मंत्रियों की मास्को में मुलाकात हुई। संयुक्त बयान में दोनों देशों के बीच नए सीबीएम समेत पांच बिंदुओं पर सहमति बनी।^[356]

21 सितंबर को छठी कमांडर-स्तरीय बैठक चुशुल-मोल्लो बीपीएम में हुई।^[357] भारतीय प्रतिनिधिमंडल में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन, दो प्रमुख जनरल, चार ब्रिगेडियर और अन्य अधिकारी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के प्रमुख और पहली बार विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे।^{[320] [358]} 14 घंटे की वार्ता के बाद, एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने "सीमावर्ती क्षेत्र में और अधिक सैनिकों को भेजने से रोकने" पर सहमति व्यक्त की।^{[321] [359]} 30 सितंबर को पांचवें दौर की राजनयिक वार्ता हुई; यह WMCC की 19वीं बैठक थी।^[360]

13 अक्टूबर को चुशुल में सैन्य कमांडरों की सातवें दौर की वार्ता हुई; हालांकि बातचीत को सकारात्मक बताया गया, लेकिन जमीनी मुद्दे और तनाव बरकरार है।^[322] 15 अक्टूबर को, जयशंकर ने कहा कि गतिरोध को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत "गोपनीय" है और इसे "पूर्वाग्रह से ग्रस्त" नहीं किया जाना चाहिए।^[361] 6 नवंबर को कोर-कमांडर-स्तरीय वार्ता के आठवें दौर के दौरान चीनी पक्ष ने डी-एस्कलेशन, डिसएंगेजमेंट और डी-इंडक्शन के लिए एक प्रस्ताव रखा।^{[323] [362]} नौवें दौर की वार्ता जनवरी 2021 में,^{[363] [324]} दसवें दौर की फरवरी 2021 में,^{[327] [326]} और ग्यारहवें दौर की वार्ता अप्रैल 2021 में हुई।^[364] फरवरी 2021 में, से सैनिकों की वापसी पैगोंग त्सो की सूचना मिली थी।^[365] 1 अगस्त 2021 को एक नई सैन्य हॉटलाइन स्थापित की गई।^[366]

2 अगस्त 2020 को एक साक्षात्कार में, भारतीय विदेश मंत्री ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "सीमा की स्थिति और हमारे संबंधों के भविष्य को अलग नहीं किया जा सकता है"।^[367] 4 अगस्त को, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों को "सुनिश्चित करना चाहिए कि मतभेद विवादों में न बढ़ें" और चीन को उम्मीद है कि भारत "द्विपक्षीय संबंधों के समग्र हितों" को बनाए रखने के लिए उनके साथ काम करेगा।^[368] 26 अगस्त को, चीनी राजदूत वेइडोंग ने कहा कि चीन को उम्मीद है कि भारत कन्फ्यूशियस संस्थानों^[369] के कामकाज को सीमा तनाव के साथ नहीं मिलाएगा - लेकिन यह इतिहास में एक "संक्षिप्त क्षण" है। हालांकि भारत का कहना था कि सीमा पर तनाव और दोनों देशों के बीच सामान्य रिश्ते आपस में जुड़े हुए

हैं।^{[370] [371]} यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज (ईएफएसएस) का कहना है कि जहां चीन ने सीमा मुद्दे और अन्य द्विपक्षीय संबंधों को अलग करने की कोशिश की है, वहीं "भारत को अब इसकी निरर्थकता, यहां तक कि प्रति-उत्पादकता का एहसास करने के लिए काफी बार परेशान किया गया है। सीमा मुद्दे को अलग-थलग करके निपटना।"^[372]

19 जून 2020 को, सर्वदलीय बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "किसी ने भी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है या किसी सैन्य चौकी पर कब्जा नहीं किया है।"^{[187] [218]} 16 सितंबर 2020 को भारतीय संसद के उच्च सदन में गृह राज्य मंत्री ने घुसपैठ के बारे में एक भाजपा सांसद के सवाल के जवाब में एक लिखित उत्तर में कहा कि "फरवरी से वहां भारत-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ के प्रयास के 47 मामले सामने आए हैं" और "पिछले छह महीनों के दौरान भारत-चीन सीमा पर कोई घुसपैठ की सूचना नहीं मिली है।"^{[373] [374]} 15 सितंबर 2020 को, भारत की संसद में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "चीन ने पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अतिक्रमण के प्रयास किए। इसमें कोंगका दर्रा, गोगरा और शामिल हैं। पैंगोंग झील का उत्तरी तट।"^[375]

29 सितंबर 2020 को, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन "अवैध" केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं देता है।^[376] अन्य राजनयिक बयानों में, 8 सितंबर को और फिर 13 अक्टूबर को,^[377] चीन ने दोहराया कि उन्होंने कभी भी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है।^{[378] [379]} चीन वर्षों से भारतीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर नियमित रूप से आपत्ति जताता रहा है।^[380] 10 अक्टूबर 2020 को ताइवान के राष्ट्रीय दिवस से पहले, नई दिल्ली में चीनी दूतावास ने राष्ट्रीय दिवस की कवरेज पर भारतीय मीडिया के लिए दिशानिर्देश जारी किए।^[381]

15 अक्टूबर को भारत ने चीन से कहा कि वह भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी न करे, चीन के बार-बार उसके बुनियादी ढांचे पर टिप्पणी करने के आग्रह को सीमा तनाव का कारण बताते हुए।^[382] राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर, तिब्बत, गिलगित, बाल्टिस्तान, अक्साई चिन और शक्सगाम घाटी की क्षेत्रीय संप्रभुता से संबंधित बयान और कार्य भी किए गए हैं।^{[383] [384] [385]} विवादित क्षेत्र में लोंगजू के पास एक नए चीनी गांव के संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जनवरी 2021 में कहा, "... चीन का अपने क्षेत्र पर सामान्य निर्माण पूरी तरह से संप्रभुता का मामला है।"^[262]

पैंगोंग त्सो

पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट से पूरी तरह से सैनिकों की वापसी फरवरी 2021 में हुई।^{[53] [54]} पैंगोंग झील पर सैनिकों की वापसी के समझौते का एक हिस्सा उन पदों से भारतीय सैनिकों की वापसी थी, जिन पर उन्होंने 29 और 30 अगस्त को चुशुल सेक्टर में नियंत्रण कर लिया था। और कैलाश रेंज स्पैंगगुर गैप और स्पैंगगुर त्सो में चीनी फिक्स्चर को देखती है।^{[319] [157] [158] [162]}

गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स

भारत ने मई 2020 की शुरुआत में यथास्थिति में बदलाव की सूचना दी।^[389] मई से जून की शुरुआत तक, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स सहित क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी के प्रयास चल रहे थे।^[389] 9 जून 2020 को, पीएलए हॉट स्प्रिंग्स में 2 किमी पीछे चला गया।^[390] हालांकि अन्य क्षेत्रों में झड़पों के बाद आगे तनाव कम नहीं हुआ, जिसमें 15/16 जून की झड़प भी शामिल है जिसके कारण तनाव हुआ था।^[391] 24 जून 2020 को, सामान्य रूप से विघटन पर फिर से सहमति बनी।^[391] जुलाई 2020 की शुरुआत तक, विघटन चल रहा था,^{[340] [342]} और 25 जुलाई 2020 को, इंडिया टुडे और एएनआई ने हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में स्थानों पर विघटन के पूरा होने के बारे में लिखा था।^{[346] [53]} फरवरी 2021 में, इंडिया टुडे के सूत्रों और अधिकारियों के अनुसार, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के अन्य स्थानों पर सैनिकों की वापसी पर अभी चर्चा होनी बाकी थी।^{[392] [54]}

बारहवीं सैन्य कमांडरों की वार्ता के बाद, गोगरा पोस्ट (पीपी 17ए) पर 4 और 5 अगस्त 2021 को विघटन हुआ।^{[388] [330]} भारतीय विश्लेषकों ने माना है कि पीपी 17ए पर बनाए गए बफर जोन के परिणामस्वरूप एलएसी पश्चिम की ओर खिसक रही है।^{[55] [56]} जबकि संयुक्त बयान में कहा गया है कि "दोनों पक्षों द्वारा क्षेत्र में बनाई गई सभी अस्थायी संरचनाओं और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है और पारस्परिक रूप से सत्यापित किया गया है", विश्लेषकों ने बताया कि चीनी संरचनाएं अभी भी उपग्रह इमेजरी के माध्यम से दिखाई दे रही हैं।^[393]

भारत की क्षेत्रीय क्षति

जुलाई 2020 में मंत्रालय-स्तरीय चर्चा के बाद दोनों पक्षों द्वारा आंशिक विघटन के बाद, कई भारतीय रक्षा विश्लेषकों ने बताया कि यह समझौता यथास्थिति की विफलता है जो अप्रैल 2020 तक मौजूद थी और यथास्थिति में वापसी की संभावना नहीं थी।^[394] इसके अलावा, भारतीय सूत्रों ने बताया है कि देपसांग के मैदानों और पैंगोंग त्सो की फिंगर 4 में टोंटी 'वाई' जंक्शन से पीछे हटने की चीनी अनिच्छा, जहां चीनी सेना भारतीय दावे वाले क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ी और सैन्य प्रतिष्ठानों का निर्माण किया, एक बाधा है। पूर्व यथास्थिति पर लौटना।^{[395] [396] [397]}

सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बड़े पैमाने पर भारतीय क्षेत्रों के अंदर बफर जोन स्थापित किए गए हैं।^[398] उदाहरण के लिए, पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर बफर जोन में, भारतीय सैनिक अब 'फिंगर-2' से 'फिंगर-8' तक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर गश्त नहीं कर सकते हैं, हालांकि भारतीय मानचित्र इस रेखा को दर्शाते हैं। 'फिंगर-8' पर वास्तविक नियंत्रण का।^[398] लद्दाख में एलएएचडीसी के एक पार्षद ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गोगरा - हॉट स्प्रिंग्स से भारतीय और चीनी सैनिकों की वापसी पूरी होने के बाद भारतीय क्षेत्र को "बफर जोन" में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा, "हमारे सैनिक न केवल पीपी-15 बल्कि पीपी-16 से भी वापस चले गए हैं, जो पिछले 50 वर्षों से हमारे पास था। (...) हमारे चारागाह अब बफर जोन बन गए हैं।"^{[2] [4]} उन्होंने कहा कि भारत की कुगांग घाटी एक विवादित क्षेत्र बन सकती है।^[3] भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम

स्वामी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत अपने ही क्षेत्र से पीछे हट गया है।^{[3] [399]} भारतीय सैन्य दिग्गजों ने कहा कि बफर जोन एक "नई यथास्थिति" का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन क्षेत्रों का निर्माण "आगे भारतीय क्षेत्र को चीनियों को सौंपने" के समान है।^[400] कर्नल अजय शुक्ला ने कहा कि अप्रैल 2020 के बाद से सभी डिसएंगेजमेंट में जो बफर जोन अस्तित्व में आए हैं, वे पूरी तरह से भारत द्वारा दावा किए गए और पहले गश्त किए गए क्षेत्र पर हैं, लेकिन अब, परिणामस्वरूप, भारत को गश्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। जहां यह पहले हो सकता था। दूसरी ओर, चीन के बफर जोन उस क्षेत्र पर नहीं हैं जिस पर चीन दावा करता है और पहले वहां गश्त करता था और इसलिए, चीन उस बिंदु तक गश्त जारी रख सकता है जहां वह पहले करता था।^[401] उन्होंने गोगरा का उदाहरण दिया, जहां चीनियों ने भारतीय क्षेत्र में 4 किमी तक घुसपैठ की और 2 किमी पीछे हट गए, जबकि अन्य 2 किमी बफर जोन बन गए हैं। इसलिए, यह बफर जोन पूरी तरह से भारतीय दावे वाले क्षेत्र पर है।^[401] कर्नल शुक्ला और अन्य भारतीय दिग्गजों ने भारतीय प्रधान मंत्री के जून 2020 के बयान की कड़ी आलोचना की जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय क्षेत्र में कोई चीनी नहीं है और न ही कभी था। यह चीनी सरकार की स्थिति का समर्थन था, और बीजिंग को सीमा उल्लंघन के आरोपों को खारिज करने और अपने पास मौजूद सभी पदों पर स्वामित्व का दावा करने की अनुमति दी।^{[400] [401]} 2020 में, भारत ने समान दूरी के विघटन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि इसका मतलब होगा "अपने पक्ष के लिए क्षेत्र का नुकसान",^[402] लेकिन 2022 में उसी प्रस्ताव पर सहमति बनी। विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 'आपसी पुलबैक समझौते' के परिणामस्वरूप भारत के लिए क्षेत्र का और अधिक नुकसान होगा, जो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में एक बफर जोन है।^[403] 2023 तक, जून 2020 से लगभग 2,000 वर्ग किमी भारतीय भूमि चीन को सौंप दी गई है।^[1] क्षेत्रीय नुकसान पर चुप्पी बनाए रखने के लिए मोदी की आलोचना की गई है।^{[404] [405]} जनवरी 2023 में, गृह मंत्रालय को लद्दाख पुलिस के इनपुट के साथ प्रस्तुत एक पेपर में कहा गया था कि भारत ने जून 2020 से पूर्वी लद्दाख में 65 गश्ती बिंदुओं में से 26 तक पहुंच खो दी है।^[406]

प्रतिक्रियाओं

भारत

गलवान झड़प के बाद, भारत भर में विभिन्न स्थानों पर चीनी झंडे और सर्वोपरि नेता शी जिनपिंग के पुतले जलाए गए और विभिन्न समूहों ने अलग-अलग तरीकों से अपना विरोध दर्ज कराया।^{[407] [408]} 3 अक्टूबर 2020 को, भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान 15 जून को गलवान में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में एक स्मारक का अनावरण किया। स्मारक पर शिलालेख में लिखा है:^{[409] [410]}

15 जून, 2020 को गलवान घाटी में, 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू ने 16 बिहार की त्वरित प्रतिक्रिया बल का नेतृत्व किया और संलग्न सैनिकों को जनरल एवाई नाला से पीएलए ओपी को हटाने और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक आगे बढ़ने का काम सौंपा। कॉलम सफलतापूर्वक पीएलए ओपी को वाई नाला से हटा दिया और पीपी 14 पर पहुंच गए जहां आईए और पीएलए सैनिकों के बीच भीषण झड़प हुई। कर्नल बी संतोष बाबू ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और उनके सैनिकों ने आमने-सामने की लड़ाई में वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, जिससे पीएलए को भारी नुकसान हुआ। आगामी लड़ाई में बीस "गलवान के वीरों" ने शहादत प्राप्त की।

यह स्मारक DSDBO रोड पर KM-120 पोस्ट पर बनाया गया है।^[410] गलवान घाटी संघर्ष में मारे गए लोगों के नाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित किए गए हैं।^[411] स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कंपनी लीडर न्यिमा तेनज़िन को 7 सितंबर 2020 को लद्दाख में 21 तोपों की सलामी के साथ सार्वजनिक अंतिम संस्कार दिया गया।^[412] न्यिमा तेनज़िन की 1962 के युद्ध की एक बारूदी सुरंग पर कदम रखने के बाद मृत्यु हो गई थी।^[413] तेनज़िन का शरीर भारतीय और तिब्बती दोनों झंडों में लपेटा गया था।^[414] अक्टूबर 2021 में, आईटीबीपी के 20 सैनिकों को एलएसी पर वीरता के लिए पदक से सम्मानित किया गया।^[415]

गतिरोध के बीच, सितंबर और अक्टूबर के दौरान, डीआरडीओ ने "35 दिनों में 10 मिसाइलों" का परीक्षण किया, भारतीय मीडिया ने कुल कम से कम 12 मिसाइलों या प्रणालियों को दागे जाने की रिपोर्ट दी। इसमें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल और हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी-रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 शामिल है। भारतीय मीडिया ने बताया कि डीआरडीओ मिसाइल परीक्षण को डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने महत्वपूर्ण माना क्योंकि यह चीन के साथ गतिरोध की पृष्ठभूमि में किया गया था। हालाँकि, यह भी नोट किया गया कि COVID-19 के कारण पिछले परीक्षणों में देरी हुई थी, जो अब आयोजित किए जा रहे थे।^{[416] [417]} गतिरोध के बीच भारत ने अपने सैन्य अधिकारियों के लिए तिब्बतशास्त्र की शिक्षा का दायरा बढ़ाने का फैसला किया।^[418]

झड़पों और गतिरोध के कारण भारत द्वारा प्रतिक्रियावादी खरीदारी की गई है।^[419] इसमें भारतीय वायु सेना द्वारा रूस से 12 सुखोई-30 एमकेआई और 21 मिकोयान मिग-29 की आपातकालीन खरीद की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है।^{[420] [421]} जुलाई में, डिफेंस ने बताया कि गलवान के बाद, भारतीय सशस्त्र बल 100 से अधिक आपातकालीन खरीद अनुबंधों पर काम कर रहे थे।^[422] जुलाई में यह बताया गया था कि भारत ऐसे हल्के टैंकों की तलाश में था जिनका इस्तेमाल लद्दाख में किया जा सके।^[423] जबकि 2009 से लद्दाख के लिए हल्के टैंकों पर ध्यान दिया गया है, 2020 में चीन के तनाव ने तात्कालिकता की भावना पैदा की।^{[423] [424]} अपने स्प्रट लाइट टैंक के लिए रूस की पेशकश के बावजूद, भारत ने लाइट टैंकों के आयात को ब्लैकलिस्ट कर दिया और एक स्वदेशी टैंक (कोड नाम "ज़ोरावर") पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से डिजाइन किया जा रहा है। टैंक के 2023 तक उत्पादन में आने की उम्मीद है।^{[425] [426]} 28 सितंबर 2020 को, रक्षा अधिग्रहण परिषद, रक्षा मंत्रालय ने फास्ट-ट्रैक खरीद के तहत, लद्दाख में सैनिकों के लिए अतिरिक्त 72,400 एसआईजी 716

का आदेश दिया; एसआईजी के पहले बैच का ऑर्डर 2019 में दिया गया था और सेना को पहले ही वितरित किया जा चुका है।^{[427] [428] [429]} आपातकालीन खरीद में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित (आईडीडीएम) श्रेणी के तहत डीआरडीओ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार भी शामिल थे।^[430]

प्रारंभ में, चीन के प्रति भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया मुख्य रूप से समाचार चैनलों पर देशभक्ति कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्रचार अपीलों तक ही सीमित थी, जिसका व्यवसायों और बिक्री पर बहुत कम वास्तविक प्रभाव पड़ा।^[431] मई में, सीमा पर हुई झड़पों के जवाब में, सोनम वांगचुक ने भारतीयों से "वॉलेट पावर" का उपयोग करने और चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की।^[432] इस अपील को प्रमुख मीडिया घरानों ने कवर किया और विभिन्न मशहूर हस्तियों ने इसका समर्थन किया।^{[432] [433]}

15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद पूरे भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया।^{[74] [434]} भारतीय रेलवे ने एक चीनी फर्म के साथ एक अनुबंध रद्द कर दिया, जबकि दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल को उन्नयन में किसी भी चीनी निर्मित उत्पाद का उपयोग नहीं करने के लिए अधिसूचित किया।^[77] मुंबई ने एक मोनोरेल अनुबंध रद्द कर दिया, जहां एकमात्र बोली लगाने वाली चीनी कंपनियां थीं; और वैकल्पिक रूप से कहा कि वह इसके बजाय एक भारतीय तकनीकी भागीदार खोजने पर ध्यान केंद्रित करेगा।^[435] 2020 के सीमा विवाद के बाद कई चीनी ठेकेदारों और फर्मों की जांच बढ़ा दी गई थी। चीनी आयात को भारतीय सीमा शुल्क पर अतिरिक्त जांच से गुजरना शुरू हुआ।^[436] जवाबी कार्रवाई में, चीन और हांगकांग में सीमा शुल्क ने भारतीय निर्यात रोक दिया।^[437] यह सुनिश्चित करने के लिए भी मांग की गई थी कि चीनी कंपनियों की भारत के रणनीतिक बाजारों तक पहुंच न हो।^[75] स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि अगर सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गंभीर है, तो चीनी कंपनियों को दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस जैसी परियोजनाएं नहीं दी जानी चाहिए।^{[76] [438]} (हालांकि, 2021 के पहले सप्ताह में, रिपोर्टें सामने आई कि एक चीनी फर्म को दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस के 5.6 किमी के निर्माण का ठेका दिया गया था।^[439]) कुछ दिनों बाद, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि चीनी कंपनियों को भारत में सड़क परियोजनाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।^{[440] [441]} हरियाणा सरकार ने एक बिजली परियोजना से संबंधित निविदा रद्द कर दी जिसमें चीनी कंपनियों ने बोली लगाई थी।^[442] उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष कार्य बल के कर्मियों को सुरक्षा कारणों से टिकटों और वीचैट सहित 52 ऐप हटाने के आदेश दिए गए थे, जबकि मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को इसके लिए एक सलाह दी गई थी।^{[443] [444]}

कई भारतीय सरकारी अधिकारियों ने कहा कि सीमा तनाव का दोनों देशों के बीच व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।^[73] गलवान की घटनाओं के बाद चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के आह्वान की बढ़ती दृश्यता के बीच, कई उद्योग विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि बहिष्कार भारत के लिए प्रतिकूल होगा, व्यापार भागीदारों को गलत संदेश देगा, और बहुत बुरा होगा। चीन पर इसका प्रभाव सीमित है, क्योंकि द्विपक्षीय और वैश्विक स्तर पर भारत तुलनात्मक रूप से बहुत छोटी व्यापार शक्ति है।^{[445] [446] [447] [448]} विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि हालांकि बहिष्कार अभियान एक अच्छी पहल थी, तत्काल भविष्य में प्रतिस्थापन उत्पाद भी उपलब्ध होने चाहिए।^[449] एक उदाहरण भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग का लिया गया है जो अपनी 70% सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री आवश्यकताओं को चीन से पूरा करता है। इस सेक्टर में डंपिंग की जांच की जा रही है।^{[450] [451]} जून के अंत तक, कुछ विश्लेषक इस बात पर सहमत थे कि भारत और चीन के बीच सीमा तनाव से मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा और कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की गति बढ़ेगी।^[449]

भारतीय सेना के बुलेटप्रूफ जैकेट में चीनी सामग्री का मुद्दा जून में गलवान की घटनाओं के बाद फिर से उठाया गया था।^[452] नीति आयोग के सदस्य और पूर्व डीआरडीओ प्रमुख वीके सारस्वत ने कहा कि यह गुणवत्ता और कीमत के कारण है कि भारतीय उत्पादों के बजाय चीनी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।^[453] 2019 में सरकार द्वारा ऑर्डर किए गए बुलेट-प्रूफ जैकेट में 40% तक चीनी सामग्री थी। 20 जून को, यह बताया गया कि भारतीय बुलेटप्रूफ जैकेट, "सर्वत्र कवच" का विकास, जो कि 100% भारत में बना है, पूरा होने के करीब है।^[454] महाराष्ट्र सरकार ने ₹ 5,000 करोड़ (2023 में ₹ 59 बिलियन या यूएस\$740 मिलियन के बराबर) मूल्य की चीनी परियोजनाओं को रोक दिया।^[455] उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने 1000 से अधिक चीन निर्मित सामानों की एक सूची निकाली है, जिस पर भारत सरकार ने आयात प्रतिबंध लगाने के लिए टिप्पणियां मांगी हैं। इससे पहले विभाग ने निजी कंपनियों से चीनी आयात की सूची सौंपने को कहा था।^{[456] [457]} लद्दाख की घटनाओं को भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से दूर रखने के अतिरिक्त कारणों के रूप में भी लिया जा रहा है जिसमें चीन की बड़ी भूमिका है।^[458]

बहिष्कार के आह्वान के बावजूद, झड़पों के तुरंत बाद भारत में चीनी स्मार्टफोन की बिक्री प्रभावित नहीं हुई। चीनी स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस का नवीनतम मॉडल गलवान झड़प के दो दिन बाद 18 जून को भारत में कुछ ही मिनटों में बिक गया।^{[459] [460]} श्याओमी इंडिया के प्रबंध निदेशक ने कहा कि सोशल मीडिया प्रतिक्रिया से बिक्री प्रभावित नहीं होगी, उन्होंने कहा कि श्याओमी हैंडसेट "भारतीय हैंडसेट कंपनियों की तुलना में अधिक भारतीय हैं" और यहां तक कि कई गैर-चीनी फोन, अमेरिकी हैंडसेट सहित लोग, चीन में निर्मित और आयातित हैं।^{[461] [462]} इसके बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने एक बयान दिया, जिसमें दावा किया गया कि Xiaomi के प्रबंध निदेशक "अपने चीनी आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे थे।" राष्ट्र का मूड।^{[464] [465]} भारत की सबसे बड़ी रसोई उपकरण निर्माता टीटीके प्रेस्टीज ने कहा कि वह 30 सितंबर से चीन से सभी आयात बंद कर देगी।^[466] 23 जून को सरकार ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को उत्पादों के लिए 'मूल देश' दिखाने का आदेश दिया था।^{[467] [468]} जुलाई में, हीरो साइकिल्स ने अपनी "चीनी उत्पादों के बहिष्कार की प्रतिबद्धता" के

हिस्से के रूप में चीन के साथ ₹ 900 करोड़ (2023 में ₹ 11 बिलियन या यूएस \$ 130 मिलियन के बराबर) की परियोजनाओं को रद्द कर दिया।^[469] अगस्त की शुरुआत में सीमा की स्थिति के बीच, भारत में प्रमुख क्रिकेट लीग, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ने शीर्षक प्रायोजक वीवो सहित चीनी प्रायोजकों को बनाए रखने का फैसला किया।^[470]^[471] विभिन्न मोर्चों पर इसके लिए बहुत आलोचना का सामना करने के बाद, वीवो ने खुद को बाहर कर लिया, संभवतः वित्त मुद्दों के साथ-साथ सीमा तनाव के कारण भी।^[472]^[473]^[474] प्रायोजन सौदा 293 मिलियन डॉलर का था।^[475] 15 अक्टूबर तक, भारत सरकार ने टेलीविजन सेट, टायर और एयर कंडीशनर सहित चीन से अधिक आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।^[476]

29 जून को, भारत सरकार ने टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउज़र, शेयरइट और Baidu मैप्स सहित 59 चीनी मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया।^[477]^[478] पीआरसी ने जवाब में मुख्य भूमि चीन में भारतीय समाचार पत्रों और वेबसाइटों को अवरुद्ध कर दिया।^[479] प्रारंभिक प्रतिबंध के बाद, सितंबर में, भारत सरकार ने देश की संप्रभुता और अखंडता का हवाला देते हुए लोकप्रिय गेमिंग ऐप, PUBG मोबाइल सहित 118 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया।^[480] नवंबर में, चौथी प्रतिबंध सूची जारी की गई, जिसमें अलीबाबा समूह के अलीएक्सप्रेस, अलीपे कैशियर और अलीबाबा वर्कबेंच सहित 43 और ऐप्स सूचीबद्ध थे।^[481] चौथी प्रतिबंध सूची के बाद, भारत सरकार द्वारा 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिनमें अलीबाबा, टेनसेंट, Baidu, सिना और बाइटडांस के स्वामित्व वाले ऐप्स शामिल थे।^[78] त्योहारी सीज़न के दौरान चीनी सामानों की बिक्री को रोकने और बदले में इसकी जगह भारतीय उत्पादों को लाने के लिए देश भर में कई पहल की गई।^[482]^[483] चीनी कंपनियों की वापसी

मार्च 2021 तक, हुआवेई भारती एयरटेल से ₹ 300 करोड़ (2023 में ₹ 353 करोड़ या यूएस \$ 44 मिलियन के बराबर) के एक और सौदे के साथ भारतीय बाजार में वापस आ गई थी।^[484] माना जाता है कि भारती एयरटेल ने आगे बढ़ने का फैसला किया क्योंकि हुआवेई पहले से ही एयरटेल के लंबी दूरी के नेटवर्क की देखभाल कर रही थी।^[485] अगस्त 2021 तक, चीनी ऐप्स, जिनमें उन कंपनियों के ऐप्स भी शामिल थे जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, भारतीय साइबरस्पेस में वापस आ गए थे।^[486]^[487]

8 अगस्त को, बिजनेस टुडे ने बताया कि भारत सरकार के सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, बहिष्कार के आह्वान के बीच, जनवरी 2020 से भारत में मुख्य भूमि चीन का निर्यात साल-दर-साल 24.7 प्रतिशत गिर गया है।^[488] यह भी बताया गया कि भारतीय बाजार में चीनी स्मार्टफोन कंपनियों की हिस्सेदारी जून तिमाही 2020 के दौरान 72 प्रतिशत तक गिर गई, जो मार्च तिमाही 2020 में 81 प्रतिशत थी।^[488]^[489]

हालाँकि, द हिंदू के एक लेख में गिरावट के लिए मुख्य रूप से भारत में COVID-19 महामारी लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया गया, चीन से आयात जुलाई में लगभग प्री-लॉकडाउन स्तर पर पहुंच गया।^[490] 9 सितंबर को, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी कि "सीमा संघर्ष भारत-चीन व्यापार को प्रभावित करने में विफल रहा" और भारत से चीन को "निर्यात में वृद्धि" हुई।^[491] 2021 में देशों के बीच कुल व्यापार 125 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया।^[492]

फरवरी 2022 में, भारत ने सीमा पर झड़पों को लेकर 54 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया।^[493]

2022 में, चीन से भारत का आयात रिकॉर्ड उंचाई पर पहुंच गया, जबकि व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से अधिक बढ़ गया।^[494]

कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश

भारत के प्रधान मंत्री ने 3 जुलाई 2020 को लद्दाख का दौरा किया जहां उन्होंने आगे के पदों पर तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों के साथ बातचीत की।^[495]

6 सितंबर को, हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट साझा किए जा रहे थे कि कैसे चुशुल और मेराक गांवों के स्थानीय लोग भारतीय सेना को पानी और अन्य आवश्यक आपूर्ति करने में मदद कर रहे हैं, जिसमें ब्लैक टॉप जैसे फ्रंट-लाइन क्षेत्र भी शामिल हैं।^[496]

17 जून को, गलवान झड़प के बाद, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, "उन कश्मीरियों को किसी प्रकार के उद्धारकर्ता के रूप में चीन की ओर देखने की इच्छा है, उन्हें केवल उड़घुर मुसलमानों की दुर्दशा के लिए Google पर खोज करने की आवश्यकता है। सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं।..."^[497] ट्वीट के बाद उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट निष्क्रिय कर दिया।^[497] ओआरएफ के एसोसिएट फेलो खालिद शाह लिखते हैं कि बड़े पैमाने पर कश्मीरी आबादी ने "चीनी जुझारूपन के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।"^[498]

श्रीनगर में पत्थरबाजों ने भारतीय सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाने के लिए "चीन आया, चीन आया" (अनुवादित चीन आ गया है, चीन आ गया है) जैसे नारे का इस्तेमाल किया, जबकि चारों ओर एक मजाक चल रहा है "चीन कोट वोट?" (अनुवाद कहाँ है)। क्या चीन पहुंच गया है?) मीम्स में शी जिनपिंग को कश्मीरी पोशाक पहने दिखाया गया है और अन्य लोग उन्हें वाज़वान पकाते हुए दिखा रहे हैं। खालिद लिखते हैं कि जबकि चीन ऑनलाइन और ऑफलाइन कई बातचीत का हिस्सा बन गया है, भारत को चिंतित होना चाहिए कि "चीनी बदमाशी की तुलना भारत सरकार के कार्यों से की जाती है।"^[498] चीन के साथ तनाव के बाद, लद्दाख में सीमा से लगे स्थानों पर संचार लाइनें काट दी गईं, जिससे संचार ब्लैकआउट हो गया, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय पार्षदों ने सरकार से लाइनों को बहाल करने का अनुरोध किया।^[499]

गलवान झड़प के बाद अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि "सोमवार की रात लद्दाख में हुई बदसूरत झड़प के बाद, यह स्वाभाविक है कि अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के निवासियों को कुछ चिंताएँ होंगी।"^[500] संसद के पूर्व सदस्य प्रेम दास राय का कहना है कि यह स्वाभाविक है कि सीमा पर रहने वाले लोग चिंतित होंगे।^[500]

भारतीय सेना के सदस्यों को युद्धकालीन वीरता पुरस्कार

जनवरी 2021 में, भारत सरकार ने गलवान संघर्ष ("ऑपरेशन स्रो लेपर्ड") के दौरान बहादुरी के लिए छह भारतीय सेना कर्मियों को सम्मानित किया। एक मरणोपरांत महावीर चक्र, दूसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता अलंकरण, और पांच वीर चक्र (चार मरणोपरांत अलंकरण) प्रदान किए गए।^{[501] [502]}

यह पता चलने के बाद कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रेजिमेंटल कमांडर क्यूई फबाओ को 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया था, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि "यह वास्तव में खेदजनक है कि चीनी पक्ष ने इसे चुना है।" ओलंपिक जैसे आयोजन का राजनीतिकरण करें। बागची ने यह भी कहा कि बीजिंग में भारतीय दूतावास के प्रभारी शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने प्रभावी रूप से ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की।^{[503] [504]} भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के सीईओ ने घोषणा की कि वे 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का प्रसारण नहीं करेंगे।^[505]

बताया गया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के महासचिव शी जिनपिंग पर गलवान घटना के बाद भी भारत के साथ सीमा तनाव पर प्रतिक्रिया देने के लिए कोई सार्वजनिक दबाव नहीं था।^[506] रॉयटर्स ने बताया कि "बीजिंग की प्रतिक्रिया सीमा के उस हिस्से पर संकट को कम करने में उसकी रुचि की ओर भी इशारा करती है जो अन्य क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, जैसे ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर दावों की तुलना में राजनीतिक रूप से कम महत्वपूर्ण है।"^[506] बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी के एक वरिष्ठ शोध साथी लॉन्ग जिंगचुन ने 25 मई को लिखा था कि "पिछले गतिरोधों के विपरीत, नवीनतम सीमा घर्षण दुर्घटना के कारण नहीं हुआ था, बल्कि नई दिल्ली का एक योजनाबद्ध कदम था। भारत स्पष्ट रूप से रहा है और निश्चित रूप से जानते हैं कि गलवान घाटी क्षेत्र चीनी क्षेत्र है।"^[507]

26 मई को, शी जिनपिंग,^[86] ने पीएलए प्रतिनिधियों की एक वार्षिक बैठक के दौरान सेना से "सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहने" और "युद्ध की तैयारी बढ़ाने" का आग्रह किया। उन्होंने 2019 में पीएलए के साथ अपनी बैठक के दौरान भी "युद्ध तैयारियों" का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने चीन की सुरक्षा और विकास के बारे में वैश्विक परिदृश्य पर गहरा बदलाव लाया है।^[507]

गलवान झड़प के बाद, 20 जून को, नई दिल्ली में चीनी दूतावास ने एक लिखित राजनयिक विरोध दर्ज किया "भारत से घटना की गहन जांच करने की मांग की ... [और] भारतीय फ्रंट-लाइन सैनिकों को सख्ती से अनुशासित किया ..."^[508] 25 जून 2020 को, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में, राजदूत सन वेइदोंग ने कहा कि "घटना पूरी तरह से भारतीय पक्ष द्वारा उकसाई गई थी और इसकी जिम्मेदारी चीनी पक्ष की नहीं है।"^[509] गलवान झड़प में चीनी हताहतों की संख्या के बारे में, सीसीपी के स्वामित्व वाले दैनिक टैब्लॉइड ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू ज़िजिन ने ट्वीट किया, "मुझे जो पता है, उसके आधार पर, चीनी पक्ष को भी गलवान घाटी में शारीरिक झड़प में हताहत होना पड़ा।" लेकिन इसके साथ कोई संख्या संलग्न नहीं की गई।^[510]

अगस्त में, चीन ने गलवान झड़प और पीएलए की मौतों से संबंधित "अफवाहें" फैलाने के लिए एक नागरिक को गिरफ्तार किया। उन्हें यह लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया था कि डोंगफेंग ऑफ-रोड कंपनी द्वारा निर्मित खराब गुणवत्ता वाले सैन्य वाहनों के कारण पीएलए सैनिकों की मौत हुई।^[511] उनकी गिरफ्तारी का उल्लेख चीनी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट Chinamil.com में किया गया था।^[512] न्यूज18 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी प्रवासियों की ओर से ऑनलाइन असहमति दिखाने वाली कई आवाजें, "बुराई" बढ़ रही हैं। लेख में सीमा विवाद, रूस के साथ चीन के गठबंधन की ताकत और अंदरूनी कलह के बारे में डेंग युवेन, हू पिंग और वांग कियानकियान की टिप्पणियों का उल्लेख है।^[513] द गार्जियन को दिए एक साक्षात्कार में, 17 अगस्त 2020 को सीसीपी से निष्कासित कै ज़िया ने कहा कि हाल ही में भारत-चीन सीमा संघर्ष और अन्य जगहों पर "संघर्ष भड़काना" शी के "चीनियों का ध्यान भटकाने" के तरीके का हिस्सा था। जनता को "घरेलू आर्थिक और सामाजिक तनाव" से बचाने के साथ-साथ "अपनी स्थिति और अधिकार को मजबूत करने" के लिए भी।^{[514] [515]} तनाव के 100 दिन पूरे होने पर राजदूत सन वीडॉन्ग ने कहा कि "सीमा गतिरोध को हल करने की जिम्मेदारी 'चीन पर नहीं' है।"^[516]

शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में चीन-दक्षिण एशिया सहयोग अनुसंधान केंद्र के महासचिव लियू ज़ोंग्यी ने 21 सितंबर 2020 को एक साक्षात्कार में कहा कि भारतीय सेना चीन की जमीन पर कब्जा कर रही है। उन्होंने डेमोकोग के पास हॉट स्पिंग्स का चीनी क्षेत्र होने का उदाहरण दिया और कहा कि यह भारतीय नियंत्रण में है क्योंकि चीन ने "भारत के कुतरने" पर पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दी।^[517] ज़ोंग्यी ने भारत पर "रात के दौरान गुप्त रूप से सड़कें बनाने और कभी-कभी प्रति दिन एक से दो किलोमीटर की गति से सड़कें विकसित करने" का भी आरोप लगाया। ज़ोंग्यी ने इसे "आगे की नीति" या "आक्रामक-रक्षात्मक" नीति का कार्यान्वयन कहा। उन्होंने सीमा तनाव को हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ा और कहा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से भी अधिक "अग्रणी चीन विरोधी ताकत" बन रहा है।^{[517] [518]} चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने 29 सितंबर को एक बार फिर कहा कि चीन भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं देता है, भारतीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर आपत्ति जताता है और चीन द्वारा नए सैन्य अड्डे बनाए जाने की खबरें झूठी हैं और प्रेरित।^{[519] [520]}

चीनी ऐप्स पर पहले प्रतिबंध के बाद, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन के साथ-साथ नई दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने प्रतिबंध पर चिंता जताते हुए बयान दिए।^[521] इसके अलावा, चीन ने 31 जुलाई 2020 को भारत को चेतावनी दी कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को "जबरन अलग करने" के परिणामस्वरूप केवल दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा,

एक हार-हार की स्थिति होगी।^{[522] [523]} नवंबर में भारत सरकार की चौथी प्रतिबंध सूची के बाद, भारत में चीनी दूतावास ने कहा, "... बाजार सिद्धांतों और डब्ल्यूटीओ नियमों के स्पष्ट उल्लंघन में ये कदम चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं।"^[524] जबकि झाओ लिजियन ने कहा कि "भारत सरकार की ज़िम्मेदारी है ... चीनी कंपनियों सहित अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करना।"^[525]

19 फरवरी 2021 और उसके बाद चीनी राज्य मीडिया ने चार सैनिकों की मौत को दर्शाया।^{[526] [527] [528]} 31 मई 2021 को, एक चीनी ब्लॉगर किउ जिमिंग को गलवान में पीएलए के नुकसान पर सवाल उठाने के लिए आठ महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी।^{[529] [530]} चार मौतों का चित्रण और साथ ही रेजिमेंटल कमांडर क्यूई फैबियाओ द्वारा राज्य-मीडिया पर उपस्थिति घटना की पहली वर्षगांठ तक जारी रही।^[529] 3 अगस्त 2021 को, चीन ने 2020 में हुई झड़पों के संबंध में सोशल मीडिया पर दो लघु वीडियो जारी किए।^[531]

साल के अंत में अपने भाषण में, स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने एक बार भारत का संदर्भ लिया, "चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखी है, और कुछ सीमा क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित किया है।" द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और विकसित करने के लिए साझा प्रतिबद्धता।"^{[532] [533]}

चीनी सैनिकों को युद्धकालीन वीरता पुरस्कार

भारत-चीन सीमा पर चीन की हरकतों के खिलाफ कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में छोटे पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।^{[537] [538]} तिब्बती-अमेरिकी, ताइवानी-अमेरिकी और भारतीय-अमेरिकी ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 'चीन का बहिष्कार', 'तिब्बत भारत के साथ खड़ा है' और 'चीनी आक्रामकता बंद करो' जैसे नारे लिखी तस्वीरियां लेकर रैली निकाली।^{[539] [540]} 10 अगस्त 2020 को, वाशिंगटन में यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल के सामने नेशनल मॉल में भारतीय-अमेरिकियों द्वारा चीनी आक्रामकता के खिलाफ एक छोटे पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के भारत के कदम की भी सराहना की और उइगरों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला।^[541]

सरकारों

ऑस्ट्रेलिया : 1 जून को भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फ़ैरेल ने कहा कि सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय तरीके से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने दक्षिण चीन सागर में चीन की मौजूदगी को लेकर भी चिंता जताई।^[542]

फ्रांस : गलवान झड़प के बाद फ्रांस के दूत ने ट्वीट कर गलवान घाटी में मारे गए भारतीयों के प्रति संवेदना और चिंता व्यक्त की।^[543] 29 जून को, फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने भारतीय रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर 20 सैनिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त की, और एलएसी तनाव पर समर्थन भी बढ़ाया, "मैं अपना दृढ़ और मैत्रीपूर्ण समर्थन व्यक्त करना चाहती हूँ।" फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के साथ "। पार्ली ने भारत के साथ फ्रांस की 'गहरी एकता' को भी दोहराया।^{[544] [545]} इसके साथ ही फ्रांस भारत को अपनी सेना का समर्थन देने वाला पहला देश बन गया।^{[545] [546]}

जर्मनी : गलवान झड़प के बाद जर्मनी के दूत ने ट्वीट किया, "गलवान में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना।"^[543] इसके अलावा, जर्मन विदेश मंत्री हेइको मास ने चीन और भारत से एक बड़े संघर्ष से बचने के लिए तनाव कम करने का आग्रह किया।^[547] 4 सितंबर को, भारत में जर्मन राजदूत, वाल्टर जे. लिंडनर ने गतिरोध के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थिति सभी के लिए "अत्यधिक खतरनाक" थी और "हाथी" और "डूंगन" दोनों को तनाव कम करना चाहिए।^[548] उन्होंने कहा कि जर्मनी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तनाव का "नतीजा" महसूस कर रहा है।^[548]

इंडोनेशिया : इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने भारत और चीन दोनों से गलवान के बाद तनाव कम करने का आह्वान किया।^[549]

इटली : भारत में इटली के राजदूत, विन्सेन्जो डी लुका ने गलवान के बाद गहरी संवेदना व्यक्त की, उन्होंने कहा, "भारत और चीन दोनों न केवल इटली के लिए, बल्कि पूरे यूरोपीय संघ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भागीदार हैं।" दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण अभिनेता हैं।"^[543]

जापान : गलवान झड़प के जवाब में, भारत में जापानी दूत सातोशी सुजुकी ने ट्वीट कर गलवान में मारे गए भारतीयों के प्रति संवेदना व्यक्त की।^[543] 18 जून को जापानी विदेश मंत्रालय ने स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया।^[550] भारत में जापानी राजदूत सातोशी सुजुकी ने 3 जुलाई को भारतीय विदेश सचिव के साथ बैठक के बाद कहा कि "जापान एलएसी पर यथास्थिति बदलने के किसी भी 'एकतरफा प्रयास' का विरोध करता है।"^{[551] [552]}

मालदीव : गलवान झड़प के जवाब में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने ट्वीट किया, "मालदीव सीमा पर हाल की झड़पों में मारे गए लोगों की जान के लिए भारत के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं परिवारों के साथ हैं।", प्रियजनों, और सैनिकों के समुदाय।"^[543]

पाकिस्तान : गलवान झड़प के बाद, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा है और "संघर्ष के लिए भारत को ज़िम्मेदार ठहराया।"^[553] पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर लद्दाख में चीन की स्थिति का समर्थन किया।^[554] भारत-चीन गतिरोध के बीच, जुलाई की शुरुआत में, भारतीय मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान में एलओसी पर 20,000 सैनिकों को स्थानांतरित कर दिया है।^[555]

रूस : दिल्ली में रूसी मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुशकिन ने 1 जून को कहा कि रूस का कहना है कि इस मुद्दे को भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए।^{[556] [557]} 2 जून को, भारत के विदेश सचिव ने भारत में रूसी राजदूत,

निकोले आर. कुदाशेव के साथ स्थिति की जानकारी दी और चर्चा की।^[558] गलवान के बाद, 17 जून को, रूस में भारत के राजदूत ने स्थिति के बारे में रूसी उप विदेश मंत्री से बात की।^[559] रूस के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेसकोव ने कहा कि स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है।^[560]

रूस ने 22 जून को भारत और चीन के साथ वर्चुअल वार्ता शुरू की।^[561]^[300] रूस ने मार्च के लिए आरआईसी त्रिपक्षीय बैठक निर्धारित की थी, लेकिन सीओवीआईडी-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई।^[561] भारत और चीन के बीच सीमा स्थिति के बारे में, रूस के विदेश मंत्री, सर्गेई लावरोव ने कहा कि बैठक के विषयों पर पहले ही सहमति हो चुकी थी और "आरआईसी एजेंडे में उन मुद्दों पर चर्चा शामिल नहीं है जो किसी देश के द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित हैं किसी अन्य सदस्य के साथ।"^[562] त्रिपक्षीय बैठक के दौरान भारत ने रूस और चीन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूसी और चीनी हितों में भारत की निस्वार्थ भागीदारी की याद दिलाई, जहां भारत ने फारसी गलियारे और हिमालय हंप के ऊपर आपूर्ति लाइनें खोलकर दोनों देशों की मदद की थी।^[563]

रूस ने तर्क दिया कि भारत-चीन टकराव दोनों देशों, यूरेशियन क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए एक "बुरा विचार" होगा। रूस ने कहा कि इस तरह के टकराव से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में चीन की वैधता को नुकसान पहुंचेगा और मौजूदा सीमित चीनी सॉफ्ट पावर में कमी आएगी। इसने शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका के शून्य टकराव का उदाहरण देते हुए दोनों देशों को सलाह दी थी कि यह बिना किसी टकराव के दोनों देशों के लिए जीतने योग्य स्थिति होगी।^[564] रूस ने तीनों देशों के रक्षा प्रमुखों की पहली बैठक आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा, जिस पर बैठक के दौरान चीन और भारत ने भी सहमति व्यक्त की। हालाँकि, रूस ने दोहराया कि चीन और भारत रूस सहित किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना द्विपक्षीय तरीकों से अपने मतभेदों को सुलझा सकते हैं।^[563]

यूनाइटेड किंगडम : भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त गलवान झड़प पर काफी चिंतित थे और उन्होंने कहा कि भारत और चीन को इसे बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए।^[565] प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने भी चिंता व्यक्त की और ब्रिटेन घाटी की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है।^[565]

संयुक्त राज्य अमेरिका : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 27 मई 2020 को चीन और भारत के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। इस प्रस्ताव को दोनों देशों ने अस्वीकार कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी एक पॉडकास्ट में इस मुद्दे को उठाया और चीन का जिक्र करते हुए कहा कि ये उस तरह की कार्रवाइयां हैं जो सत्तावादी शासन ने की हैं और इनका वास्तविक प्रभाव हो सकता है।^[566]^[567] यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के प्रमुख एलियट एंगेल ने भी स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "चीन एक बार फिर दिखा रहा है कि वह अपने पड़ोसियों पर धौंस जमाने को तैयार है।"^[568] 2 जून को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन-भारत सीमा स्थिति पर चर्चा की।^[569] गलवान के बाद, अमेरिकी विदेश सचिव ने ट्वीट कर जान गंवाने वाले भारत के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की;^[570] जबकि अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है।^[543] 18 जून को मिच मैककोनेल ने कहा कि "ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, पीएलए ने चीन और भारत के बीच 1962 में युद्ध के बाद से सबसे हिंसक झड़प को उकसाया है।"^[96]

20 जून को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि तनाव को हल करने में सहायता के लिए अमेरिका चीन और भारत दोनों के संपर्क में है।^[571] 25 जून को, माइक पोम्पियो ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की हालिया कार्रवाइयों के कारण अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी से बाहर ले जाया जा रहा है और भारत और अन्य अमेरिकी सहयोगी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फिर से तैनात किया जा रहा है और उन्हें कार्रवाई करने के लिए उचित रूप से तैनात किया जा रहा है। PLA के प्रतिकार के रूप में।^[572]

1 जुलाई को, भारत द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद, माइक पोम्पियो ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस कदम से भारत की 'संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा' को बढ़ावा मिलेगा।^[573] 24 सितंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर चीन और भारत के बीच मार्च 2021 में नई दिल्ली में अमेरिकी रक्षा सचिव और भारतीय रक्षा मंत्री। अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा, "... हमने कभी नहीं सोचा था कि भारत और चीन युद्ध की दहलीज पर थे ..."^[577]^[578] दिसंबर में, यूएस-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में चीन द्वारा गलवान घटना की योजना बनाने की ओर इशारा किया गया था,^[579] "कुछ सबूतों से पता चलता है कि चीनी सरकार ने घटना की योजना बनाई थी, जिसमें संभावित रूप से मृत्यु की संभावना भी शामिल थी।"^[580]^[581] 23 मार्च 2021 को, एडमिरल जॉन सी. एक्विलिनो ने सीनेट सशस्त्र सेवा समिति को बताया कि भारत-चीन का विश्वास अब तक के सबसे निचले स्तर पर है।^[582]

तिब्बत : राष्ट्रपति लोबसांग सांगेय ने सीमा पर झड़पों से संबंधित बयान देते हुए कहा कि "तिब्बत के साथ जो हुआ वह भारत के साथ हो सकता है" और "भारत सरकार को चीन पर अपनी नीतियों में तिब्बत को प्रमुख मुद्दों में से एक बनाना चाहिए।"^[583]^[584]^[585]

यूरोपीय संघ : 15 जून को गलवान झड़प के बाद, यूरोपीय संघ के प्रवक्ता वर्जिनी बट्टू-हेनरिकसन ने तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया।^[586]

संयुक्त राष्ट्र : गलवान झड़प के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया।^[586]^[372]

19 जून 2020 को ताइपे टाइम्स में "ताइवान को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए" शीर्षक से एक संपादकीय प्रकाशित किया गया था। लेख में भारत-चीन सीमा झड़पों का विश्लेषण किया गया था; और यह कहकर समाप्त किया कि "ताइवान को चीनी विस्तारवाद को रोकने और शी को वापस उसके डिब्बे में डालने के लिए भारत के साथ संबंध, विशेष रूप से आर्थिक, सैन्य और खुफिया संबंधों को गहरा करना चाहिए।"^[587]

यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज (EFSAS) ने 7 अगस्त 2020 को लिखा कि चीनी आक्रामकता पर भारत की प्रतिक्रिया ने "चीन को आश्चर्यचकित" कर दिया है।^[588] जुलाई की शुरुआत में पिछली टिप्पणी में, ईएफएसएस ने कहा था कि चीन को यह एहसास होना चाहिए कि यदि वह भारत को एक कोने में रहने के लिए मजबूर करता है, तो भारत "उन राष्ट्रों के बढ़ते समूह में शामिल हो जाएगा जो चीन को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं।" आदेश दें और कानून के शासन का पालन करें", चाहे भारत उस रास्ते पर चलना चाहे या न चाहे।^[589] सितंबर की शुरुआत में, ईएफएसएस ने कहा कि लद्दाख में भारत की सामरिक प्रतिक्रियाओं ने "चीन को अपनी ही बनाई रेत में फंसा दिया है।"^[590]

19 सितंबर 2020 को, निक्केई एशियन रिव्यू और हिंदुस्तान टाइम्स के एक लेख में कहा गया कि 2020 में जब दुनिया जुलाई से सितंबर तक अमेरिका और चीन को दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास करते देखने में व्यस्त थी, तो ध्यान भटक गया, "बीजिंग व्यस्त था हिमालय में भारत के साथ वास्तविक जीवन के गतिरोध में।"^{[591] [592]}

1,000 से अधिक अमेरिकियों के एक सर्वेक्षण (1 सितंबर 2020 को रिपोर्ट किया गया) में पाया गया कि "63 प्रतिशत से अधिक अमेरिकी सैन्य संघर्ष में शामिल होने पर न तो चीन और न ही भारत का समर्थन करते हैं। आर्थिक संघर्ष के मामले में, 60.6 प्रतिशत उत्तरदाता किसी हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया।"^[593]

9 सितंबर 2020 को जापान और भारत ने अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने 4 जून 2020 को एक समान म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (MLSA) पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ, भारत ने चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) के सभी भागीदारों के साथ सैन्य लॉजिस्टिक्स साझाकरण समझौता किया है।^[283]

जून में, मीडिया रिपोर्टें सामने आने लगीं कि भारत सूचना और धारणा युद्ध में चीन से हार रहा है।^{[594] [595] [596]} चीन का सूचना युद्ध भारत को आक्रामक के रूप में चित्रित करने की कोशिश पर केंद्रित था और साथ ही चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति पर बार-बार जोर देने के लिए राज्य मीडिया का इस्तेमाल किया।^{[597] [598]} 17 जुलाई 2020 को न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख में कहा गया कि भारतीय सैनिकों को लगा कि "भारत ने अपने मौन दृष्टिकोण के साथ, चीन को कथा पर हावी होने की अनुमति दी।"^[596] पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध सूचना युद्ध में चीन की मदद की है।^[599]

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के पूर्व निदेशक तारा कार्था ने अगस्त 2020 में झड़पों के दौरान चीन के साइ-ऑफ्स और प्रचार पर लिखा था। उन्होंने चीन द्वारा "मजबूत मीडिया मैसेजिंग" के उपयोग पर ध्यान दिया, जैसे "हुबेई प्रांत से भारतीय सीमाओं तक हवाई और ट्रेन द्वारा सैनिकों की तीव्र लामबंदी" के वीडियो। वह बताती हैं कि सैनिक कोरोनावायरस के मूल केंद्र वुहान क्षेत्र (हुबेई का एक उप-प्रांतीय शहर) से थे और "तेज लामबंदी" का मतलब यह भी होगा कि सैनिक पूर्वी के उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के मैदान के लिए अभ्यस्त नहीं थे। लद्दाख. एक अन्य वीडियो Z-10 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की तैनाती का था। कार्था का कहना है कि मूल Z-10 में "कम शक्ति वाले इंजन हैं (जो इसे उच्च ऊंचाई के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं)" और यहां तक कि पाकिस्तान ने भी चीनी वेरिएंट के बजाय अमेरिकी और तुर्की विमानों को प्राथमिकता दी।^[600]

कार्था ने चीन द्वारा प्रचार के अन्य प्रयासों का उल्लेख किया है, जिसमें कराटे सेनानियों को तैनात करने की रिपोर्ट, नौसेना कौशल की क्षमताएं, शी द्वारा 'पावर मैसेजिंग' जैसे पीएलए को युद्ध के लिए तैयार होने का निर्देश, होउ जैसे "भेड़िया योद्धाओं" का उपयोग शामिल है। यांकी, नेपाल में चीनी राजदूत; जबकि चीन के विदेश मंत्री जैसे अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से दुनिया के व्यापारिक समुदाय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए बयान दिए जाते हैं।^[600] हिंदुस्तान टाइम्स ने नोट किया कि डोकलाम गतिरोध के दौरान पीएलए द्वारा इस्तेमाल की गई अधिकांश साइ-ऑफ्स रणनीति यहां फिर से देखी जा रही है।^[601] इंडिया टुडे ने नोट किया कि पीएलए ने उन स्थानों पर फायरिंग अभ्यास भी किया है जहां से भारतीय सैनिक आवाजें सुन सकते हैं।^[602]

निष्कर्ष

चीनी राज्य मीडिया ने विवाद पर बहुत कम या कोई ध्यान नहीं दिया है और झड़पों को कम महत्व दिया है। गतिरोध के पहले महीने में, चाइना डेली और पीपल्स डेली में केवल एक संपादकीय अंश था।^[603] पीपल्स डेली और पीएलए डेली ने गलवान झड़प को कवर नहीं किया, जबकि सीसीपी के स्वामित्व वाले टैब्लॉइड ग्लोबल टाइम्स (चीनी) ने इसे पेज 16 पर छापा।^[604] राज्य प्रसारक चाइना सेंट्रल टेलीविजन (सीसीटीवी) ने आधिकारिक सैन्य बयान जारी किया बिना किसी अतिरिक्त कवरेज के सोशल मीडिया पर।^[604] ग्लोबल टाइम्स ने कई राय लेख और एक संपादकीय प्रकाशित किया जिसमें सवाल उठाया गया कि चीन ने सार्वजनिक रूप से अपनी मृत्यु का खुलासा क्यों नहीं किया।^{[604] [603] [605]}

चीन के विश्लेषक यूं सुन ने बताया कि सीमा विवाद के बारे में चीन के अंग्रेजी मीडिया में भले ही बहुत कम जानकारी हो, लेकिन चीनी भाषा मीडिया में बहुत अधिक विश्लेषण है।^[606] हालांकि चीनी राज्य मीडिया ने प्रधान मंत्री मोदी के 19 जून के बयान का स्वागत किया।^[187] ग्लोबल टाइम्स ने शंघाई में फुडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर लिन मिनवांग के हवाले से कहा कि "मोदी की टिप्पणी तनाव कम करने में बहुत मददगार होगी क्योंकि भारत के प्रधान मंत्री के रूप में, उन्होंने हटा दिया है कट्टरपंथियों के लिए चीन पर आगे आरोप लगाने का नैतिक आधार।"^[607] जून के अंत में चीन ने सभी भारतीय मीडिया और समाचार पत्र वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया।^{[608] [609]}

भारत में, 15 जून की झड़प से पहले, कुछ भारतीय मीडियाकर्मियों और रक्षा विश्लेषकों ने चीनी घुसपैठ की सीमा को कम करके आंका था।^[610] हालांकि 15 जून को गलवान में हुई झड़प के बाद लगभग सभी मुख्यधारा के अखबारों ने गलवान घटना की कहानियों को पहले पन्ने के साथ-साथ कई पेजों पर प्रकाशित किया।^[611] झड़प के बाद, टाइम्स नाउ ने एक सूची प्रकाशित की

जिसमें कहा गया कि इसमें उन चीनी सैनिकों के नाम थे जो झड़प में मारे गए थे, लेकिन आगाह किया कि जानकारी "फर्जी फॉरवर्ड हो सकती है"; बाद में कई स्रोतों ने कहा कि यह फर्जी खबर थी।^{[612] [613] [614]} भारतीय मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई एक और सूची जिसमें कहा गया था कि कार्गो में मारे गए चीनी सैनिकों को भी दिखाया गया था, चीनी प्रवक्ता झाओ लिजियन ने इसे फर्जी खबर बताया था।^[615]

6 जून को कमांडरों की बैठक से पहले, कथित तौर पर चीनी राज्य-नियंत्रित मीडिया के साथ-साथ निगमों द्वारा दुष्प्रचार अभियान चलाए गए थे। चीनी प्रसारकों ने सीमा पर सैन्य युद्धाभ्यास दिखाया, जो कथित तौर पर भारत को डराने के लिए बनाया गया था।^[616] गलवान झड़प के बाद, द न्यूयॉर्क टाइम्स^[617] और द गार्जियन में अंतर्राष्ट्रीय कवरेज ने दोनों देशों के नेताओं के "राष्ट्रवादी" चरित्र और "विस्तारवादी राष्ट्रवाद से उत्पन्न खतरों" पर टिप्पणी की।^[618] बीबीसी ने गलवान की स्थिति को "चट्टानों और डंडों के साथ असाधारण वृद्धि" के रूप में वर्णित किया।^{[619] [620]}

भारतीय और चीनी दोनों हेंडलों से सीमा घटनाओं के संबंध में बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें थीं।^[621] सोशल मीडिया क्षेत्र में, चीनी उपयोगकर्ताओं ने भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मीम्स का इस्तेमाल किया।^[621] यह बताया गया कि भारतीय उपयोगकर्ताओं को भारत पर हमला करने के लिए बनाए गए चीनी भाषा के मीम्स को समझने में कठिनाई हुई।^[621] ट्रेन को मारते हुए राम की एक ताइवानी छवि भारतीय सोशल मीडिया क्षेत्र में वायरल थी।^[621] टिकटॉक पर सीमा तनाव से संबंधित वीडियो पर "छाया प्रतिबंध" लगाने की सूचना मिली थी। वीबो और वीचैट जैसी चीनी सोशल मीडिया कंपनियों से भारत के बयान हटा दिए गए।^{[622] [623] [624]}

संदर्भ

1. सिद्दीकी, इमरान अहमद (16 जून 2023)। "अधीनता और समर्पण: सैन्य दिग्गजों ने गलवान पर मोदी सरकार की लगातार चुप्पी की आलोचना की। टेलीग्राफ इंडिया।
2. ^ ए बी "वीडियो | 'क्षेत्र समाप्त हो गया, चरागाह भूमि अब बफर जोन': सैनिकों की वापसी पर लद्दाख नेता"। 9 अक्टूबर 2022 को लिया गया।
3. ^ ए बी सी भौमिक, अनिर्बान; रे, कल्याण (14 सितंबर 2022)। "एलएसी पर वापसी इस चर्चा के बीच समाप्त हुई कि भारत हार गया है"। डेक्कन हेराल्ड। 9 अक्टूबर 2022 को लिया गया।
4. ^ ए बी सिंह, विजेता (20 सितंबर 2022)। एलएसी की सीमा से लगे गांव के प्रमुख का कहना है, "चरागाह भूमि बफर जोन में बदल रही है"। द हिंदू। 22 नवंबर 2022 को लिया गया।
5. ^ "हिमालय में खूनी गर्मी के दौरान चीन ने भारत पर बढ़त हासिल की"। ब्लूमबर्ग डॉट कॉम। 1 नवंबर 2020. 22 नवंबर 2022 को लिया गया।
6. ^ बोम्माकांति, कार्तिक। "चीन ने अभी तक भारत-चीन सीमा पर यथास्थिति बहाल नहीं की है"। ओआरएफ. 22 नवंबर 2022 को लिया गया।
7. ^ "पूर्वी लद्दाख में स्थिति सामान्य होने के लिए यथास्थिति पर लौटना जरूरी: वायुसेना प्रमुख"। www.telegraphindia.com। 22 नवंबर 2022 को लिया गया।
8. ^ ए बी सी "चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना मिग-29 के लड़ाकू विमानों को उत्तर की ओर ले जाएगी"। हिंदुस्तान टाइम्स। 21 जुलाई 2020। 21 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त।
9. ^ "एलएसी पर तनाव के बीच एयर मार्शल विवेक राम चौधरी पश्चिमी वायु कमान की कमान संभालेंगे"। हिंदुस्तान टाइम्स। 24 जुलाई 2020। 1 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त।
10. ^ ए बी "गलवान घाटी आमने-सामने: तनाव कम करने के लिए भारतीय, चीनी सैन्य अधिकारी मिले"। हिंदुस्तान टाइम्स। 18 जून 2020। 18 जून 2020 को पुनःप्राप्त।
11. ^ नेगी, मंजीत सिंह (13 अक्टूबर 2020)। "लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ने फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर के रूप में पदभार संभाला"। इंडिया टुडे। 24 अक्टूबर 2020 को लिया गया।
12. ^ भौमिक, अनिर्बान (18 जून 2020)। "गलवान घाटी: भारतीय, चीनी राजनयिक जल्द ही वीडियो-कॉन्फ्रेंस करेंगे"। डेक्कन हेराल्ड। 18 जून 2020 को पुनःप्राप्त।
13. ^ "रियर एडमिरल फिलिपोज जॉर्ज पाइनुमूटिल, एनएम ने फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन (FONA) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया"। 26 फरवरी 2019। 21 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त।
14. ^ "आईजीपी लद्दाख ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की"। दैनिक एक्सेलसियर। 9 अप्रैल 2020. 19 जून 2020 को पुनःप्राप्त।
15. ^ कक्कड़, मेजर जनरल हर्ष (16 जनवरी 2022)। "भारत-चीन गतिरोध: तनाव बढ़ने की संभावना कैसे कम हो गई है लेकिन निरंतर गतिरोध बढ़ गया है"। फ़र्स्टपोस्ट। 7 फरवरी 2022 को लिया गया।
16. ^ स्वामी, प्रवीण (23 जून 2020)। "पीएलए ने सीमा समझौतों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला किया"। न्यूज18 इंडिया. 7 फरवरी 2022 को लिया गया।
17. ^ "पूर्वी लद्दाख में भारत, चीनी सैनिकों का आमना-सामना, दोनों तरफ हताहत"। एशिया समाचार। 16 जून 2020. 16 जून 2020 को मूल से संग्रहीत। 17 जून 2020 को लिया गया।
18. ^ ए बी सी डी "लद्दाख गतिरोध में शामिल चीनी जनरल"। Rediff.com। 13 जून 2020। 19 जून 2020 को पुनःप्राप्त।

19. ^ "शी ने सैन्य, सशस्त्र पुलिस अधिकारियों को बढ़ावा देने के आदेश प्रस्तुत किए"। सिन्हुआनेट। 18 दिसंबर 2021। 14 जून 2021 को लिया गया।
20. ^ "पीएलए ने भारत-चीन एलएसी विवाद की 'प्रतिक्रिया' में झिंजियांग की सैन्य इकाइयों का आधुनिकीकरण किया"। हिंदुस्तान टाइम्स। 17 मई 2021। 14 जून 2021 को लिया गया।
21. ^ "ऐतिहासिक कदम में, भारत ने चीन सीमा पर 50,000 और सैनिक तैनात किए"। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। 28 जून 2021। 7 फरवरी 2022 को लिया गया।
22. ^ "भारत-चीन सीमा गतिरोध: चीन ने लद्दाख में पैगोंग झील पर पुल का निर्माण किया"। लाइवमिंट। 4 जनवरी 2022। 7 फरवरी 2022 को लिया गया। ...करीब 60,000 सैनिक तैनात...
23. ^ ए बी "लद्दाख, सिक्किम में भारत, चीन के बीच झड़प, कई लोग घायल"। द ट्रिब्यून। भारत। 10 मई 2020.
24. ^ ए बी माइकल सफी और हन्ना एलिस-पीटरसन (16 जून 2020)। "भारत का कहना है कि चीन के साथ विवादित हिमालयी सीमा पर 20 सैनिक मारे गए"। अभिभावक। 16 जून 2020 को पुनःप्राप्त.
25. ^ ए बी सी डी ई हैदर, सुहासिनी; पेरी, दिनाकर (18 जून 2020)। "लद्दाख आमना-सामना | झड़प के कुछ दिनों बाद, चीन ने 10 भारतीय सैनिकों को मुक्त कर दिया"। द हिंदू। आईएसएसएन 0971-751X. मूल से 19 जून 2020 को संग्रहीत। 19 जून 2020 को पुनःप्राप्त.
26. ^ ए बी सी डी "सेना के अधिकारियों का कहना है कि लद्दाख में झड़प में बुरी तरह घायल हुए 76 सैनिक स्थिर और स्वस्थ हो रहे हैं"। आउटलुक। 19 जून 2020. 19 जून 2020 को पुनःप्राप्त.
27. ^ ए बी "रिपोर्टों में कहा गया है कि 10 को रिहा कर दिया गया है, चीन ने भारतीय सैनिकों को हिरासत में लेने से इनकार किया है"। अल जज़ीरा। 19 जून 2020। 21 जून 2020 को पुनःप्राप्त.
28. ^ ए बी रॉय, राजेश (19 जून 2020)। "चीन ने घातक संघर्ष में पकड़े गए भारतीय सैनिकों को लौटाया"। वॉल स्ट्रीट जर्नल। 19 जून 2020 को पुनःप्राप्त.
29. ^ ए बी मेयर्स, स्टीवन ली; अबी-हबीब, मारिया; गेटलमेन, जेफरी (17 जून 2020)। "चीन-भारत संघर्ष में, दो राष्ट्रवादी नेताओं के पास देने के लिए बहुत कम जगह है"। न्यूयॉर्क टाइम्स। 19 जून 2020 को पुनःप्राप्त.
30. ^ ए बी श्रीवास्तव, राहुल (25 जनवरी 2021)। "सिक्किम के नाकू ला में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीटा, पीछे धकेला; सेना ने जारी किया बयान"। इंडिया टुडे। 7 फरवरी 2022 को लिया गया।
31. ^ ए बी ली मायर्स, स्टीवन (19 फरवरी 2021)। "चीन ने पिछले साल भारत के साथ सीमा संघर्ष में 4 मौतों को स्वीकार किया"। एनवाई टाइम्स। 19 फरवरी 2021 को लिया गया।: "लेख [पीएलए डेली में] ने चार मौतों को विस्तृत गिनती के रूप में प्रस्तुत नहीं किया।"
32. ^ ए बी चीन ने जून 2020 में भारत के साथ सीमा संघर्ष में मारे गए चार सैनिकों का खुलासा किया, रॉयटर्स, 19 फरवरी 2021। 'यह पूछे जाने पर कि क्या इसका मतलब यह है कि जून की झड़प के बाद आठ महीने तक चले पूरे गतिरोध के दौरान कोई अन्य चीनी सैनिक नहीं मरा, हुआ [चुनयिंग] ने कहा : "हां, मैं समझता हूं कि यही मामला है।"
33. ^ ए बी सी सूद, वेदिका; वेस्टकाट, बेन (11 मई 2020)। "चीनी और भारतीय सैनिक 'आक्रामक' सीमा पार झड़प में शामिल हैं"। सीएनएन। 12 मई 2020 को लिया गया.
34. ^ ए बी फिलिप, स्नेहीश एलेक्स (1 मार्च 2021)। "4, 9 या 14? यहां तक कि चीन को भी 'यकीन नहीं' है कि गलवान घाटी में कितने पीएलए सैनिक मारे गए"। दिप्रिंट। 1 मार्च 2021 को लिया गया।
35. ^ ए बी कृष्णन, अनंत (19 फरवरी 2021)। "चीन का कहना है कि गलवान झड़प में उसके चार सैनिक मारे गए"। द हिंदू। हालांकि, रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि पीएलए को कुल कितनी चोटें आईं, केवल रेजिमेंटल कमांडर की चोट का उल्लेख किया गया है। पीएलए को कहीं अधिक संख्या में घायल होने की संभावना है, भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने झड़प के बाद स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे लगभग 60 चीनी सैनिकों की गिनती की।
36. ^ ए बी सी "लद्दाख में भारत के साथ झड़प के दौरान चीन को 43 लोग हताहत हुए: रिपोर्ट"। इंडिया टुडे। 16 जून 2020। 17 जून 2020 को लिया गया।
37. ^ बनर्जी, अरित्रा (12 अक्टूबर 2021)। "भारतीय सेना ने 200 पीएलए सैनिकों को हिरासत में लिया; चीन ने जवाबी कार्रवाई में गलवान संघर्ष की तस्वीरें जारी कीं -"। यूरोशियन टाइम्स.
38. ^ ए बी सी डी बाली, पवन (20 जून 2020)। जनरल वीके सिंह का दावा है, "भारत ने गलवान घाटी में पकड़े गए चीनी सैनिकों को भी रिहा कर दिया।" डेक्कन क्रॉनिकल।
39. ^ ए बी सी डी "लद्दाख के चुशूल सेक्टर में पकड़ा गया चीनी सैनिक, लौटाया जाएगा"। भारत आज. 9 जनवरी 2021.
40. ^ ए बी सी शिंकमैन, पॉल डी. (16 जून 2020)। "भारत, चीन दशकों में पहली घातक झड़प में आमने-सामने"। अमेरिकी समाचार और विश्व रिपोर्ट। 16 जून 2020 को पुनःप्राप्त.
41. ^ ए बी सी "लद्दाख आमने-सामने | सरकारी सूत्रों ने अमेरिकी खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए दावा किया कि चीन को 35 हताहतों का सामना करना पड़ा"। द हिंदू। पीटीआई. 17 जून 2020. ISSN 0971-751X। 27 जुलाई 2020 को



- पुनःप्राप्त. अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, चीनी सेना को 35 हताहतों का सामना करना पड़ा... यह आंकड़ा मारे गए और गंभीर रूप से घायल हुए सैनिकों की कुल संख्या का संयोजन हो सकता है
42. ^{एबी} ली मायर्स, स्टीवन (19 फरवरी 2021)। "चीन ने पिछले साल भारत के साथ सीमा संघर्ष में 4 मौतों को स्वीकार किया"। एनवाई टाइम्स। 19 फरवरी 2021 को लिया गया।: "एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने पिछली गर्मियों में कहा था कि चीन ने जानबूझकर अपने सैनिकों की मौत को छुपाया था, जिससे पता चलता है कि 20 से 30 के बीच सैनिक मारे गए थे।"



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT



+91 99405 72462



+91 63819 07438



ijmrsetm@gmail.com

www.ijmrsetm.com